सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
इंदौर
गुरुवार, 28 मई, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 235, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

बेतहाशा गिर रहे रूपए की चाल आखिर कैसे सुधरेगी?

अरविंद मोहन

जिस दिन डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत लगातार तीसरे दिन बढ़ी और दस दिनों के अंदर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ उस दिन पेट्रोल डीजल की चर्चा छोड़कर डॉलर रुपये की बात करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी लगता है कि यह मोदी सरकार का सर्वाधिक उपेक्षित प्रबंधन का विषय रहा है। कहना न होगा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार की हर कमजोरी को निशाना बनाने वाले नरेंद्र मोदी डॉलर की गिरावट को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था।

अगर मोदी जी और उनके शिष्य या उस्ताद बाबा रामदेव मोदी राज में डॉलर की औकात बताने वाला रेट लाने की बात करते थे तो अरुण जेटली जैसे लोग रुपये की गिरावट को मुल्क की इज्जत की गिरावट से जोड़ रहे थे। अब यह हिसाब लगाने की भी चीज नहीं रह गया कि तब डॉलर का रेट क्या था और अब क्या है। और डॉलर या बड़ी मुद्राओं के मुकाबले रुपये की गिरावट को निर्यात के लिए लाभकर बताने वाले भी अब स्वीकार करने लगे हैं कि आज की स्थिति नुकसानदेह हो गई है। और तो और रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मलहोत्रा ने भी एक आर्थिक अखबार को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि रुपया 'ओवरवैल्यू' नहीं'अंडरवैल्यू' है।

रिजर्व बैंक गवर्नर के इस इंटरव्यू के अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक आयोजन में कहा कि तीन 'एफ'- हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं जिनमें फ़ोरेन करेंसी भी एक है। इन दोनों शीर्षस्थ लोगों के इन बयानों के संग संग रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा ऐसे प्रयासों की झलक भी मुद्रा बाजार में दिखी जिससे रुपया कुछ स्थिर हो या चढ़े। जिन तीन दिनों के सुधार की चर्चा ऊपर है वे भी तेल के आयात बजट को कम करते हैं। लेकिन इस सरकारी कवायद में कितना कुछ गंभीर है और कितना तात्कालिक, कहना मुश्किल है। बल्कि जब भरभराकर गिरेगा, ऐसा बाजार के कथित तकनीकी विशेषज्ञों का हिसाब रहता है जो शेयर बाजार के मामले में ज्यादा लागू होता है। पर जाहिर तौर पर शेयर हों या मुद्रा वे तकनीकी आधार पर नहीं चलते। वे तो आर्थिक कामकाज और उनकी सफलता विफलता के साथ सरकारी फैसलों, प्राकृतिक कारणों से लेकर बाजार की मांग समेत ठोस आर्थिक कारणों से चलते हैं।

हमारी मुश्किल यह है कि हमने रुपये और उससे भी ज्यादा शेयर बाजार को सिर्फ प्रबंधन का मामला बनाने का प्रयास किया है। अधिकांश निवेश साझा कोषों के माध्यम से होने लगा है और उसका धन तरह-तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें बाजार में निवेश और घर बैठे मोटी कमाई के लालच का हिस्सा काफी बड़ा होगा। लेकिन जब वेतन और प्रोविडेन्ट फंड से साझा कोषों को जोड़ा जाए और बाजार की हर गिरावट पर इन साझा कोषों को कठपुतलियों की तरह संचालित करके एक नकली उभार या उफान दिखाया जाए तो यह खेल एक सीमा तक ही चल सकता है।

उदारीकरण की शुरुआत से यह खेल शुरू हुआ है, लेकिन अब तो बाजार कुछ अदृश्य 'तेजड़ियों' की पूरी गिरफ्त में आ गया है। और यह हमारे निवेशकों और साझा कोष के प्रबंधकों को चाहे जिस वजह से समझ न आये लेकिन बाजार जानने वाला हर आदमी जानता है कि हमारे अधिकांश शेयर अपने वास्तविक मूल्य से काफी ऊपर चल रहे हैं। इस एहसास के साथ पिछले साल डेढ़ साल में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी पूंजी निकाली है। डॉलर की मांग बढ़ने और रुपये के मुकाबले चढ़ने की एक बड़ी वजह विदेशी पूंजी को निकालना भी है। सब कुछ जानकर भी इस पूंजी पलायन को थामने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसकी जगह साझा कोषों के माध्यम से देसी पूंजी भरी गई है। डॉलर की मांग सिर्फ विदेशी संस्थागत निवेशकों के हाथ खींचने से ही नहीं बढ़ी है। यह विदेश व्यापार के असंतुलन और चालू खाते के घाटे से भी जुड़ा मामला है। हमारी कंपनियों ने विदेशों में निवेश किया है जो सामान्य ढंग से अच्छी बात है, लेकिन खास परिस्थिति में चिंता की भी बात है। हमारे बच्चे कम संख्या में विदेश पढ़ने जा रहे हैं, लोगों की विदेश यात्राओं पर खर्च कम हुआ है। इनसे राहत मिलनी चाहिए थी और मिली भी होगी, पर गिरावट का बढ़ना ज्यादा चिंता की बात है। अगर हमारी मुद्रा साल भर में ग्यारह फीसदी तक गिरी है तो इसे सिर्फ खाड़ी युद्ध का असर बताना बहानेबाजी है। इसी दौर में दुनिया के कई देशों की मुद्राएं मजबूत हुई हैं तो कई की गिरावट हमसे बहुत कम रही है। वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की मुद्राओं में सुधार हुआ है। यह निश्चित है कि खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी करके हमारे विदेश व्यापार के घाटे का बोझ बढ़ा दिया है लेकिन यह भी सच है कि इस अवधि में हमें वैसा संकट नहीं झेलना पड़ा जैसा काफी सारे देशों में देखने में आया है। पर तेल का खेल हमारी सरकार जिस तरह खेलती रही है वह सामान्य तर्क से परे है। हम रूसी तेल छोड़कर वेनेजुएला से तेल लें और वह भी ज्यादा गंदगी वाला, ज्यादा ढुलाई खर्च वाला, यह किसे समझ आएगा। और रूस से तेल लेने न लेने का फैसला अचानक ट्रम्प क्यों करने लगे हैं और हम उसे मानने लगे हैं, यह समझना और मुश्किल है। चुनाव हो तो तेल की कीमत न बढाई जाएं और चुनाव बीतते ही कीमतें धारावाहिक हिसाब से बढ़ें, यह बात भी हैरान करती है। जीएसटी को आये दसेक साल हो गए, जाने कितने रिवीजन हो गए लेकिन पेट्रोलियम को उसके दायरे में कब लाया जाएगा, अभी भी अस्पष्ट है। और तब तक सरकार कई तरह के करों के सहारे हर साल लाखों करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूलती जा रही है। ग्यारह बारह वर्षों में चालीस लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त वसूली का अनुमान है। और अब प्रधानमंत्री आर्थिक तरक्की की शान की जगह आर्थिक मुश्किलों का रोना क्यों रोने लगे हैं। यह कीमतें बढ़ाने के बहाने के तौर पर देखा जा रहा है। सो बारह साल में अगर डॉलर की तेजी थामने और रुपये को सम्मानजनक स्थान पर ले जाने का कोई एक भी गंभीर प्रयास नहीं हुआ है तो अभी भी वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर की बातचीत में गंभीरता नहीं दिखती। सारा नज़रिया झाड़-फूँक वाला है, हर स्थिति का राजनैतिक लाभ लेने वाला है। ऐसे में यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

समर्थ सीबीआई रिमांड पर, गिरीबाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित

ट्विशा केस

मप्र सरकार ने जमानत पर आपत्ति जताई, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप

जबलपुर/भोपाल (एजेंसी)। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एसआईटी ने आरोपी पति समर्थ सिंह को बुधवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है।

वहीं, रिटायर्ड जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। एमपी सरकार और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने अग्रिम जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ट्विशा के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पैरवी की।

जांच अब सीडीआर, मोबाइल लोकेशन जैसे डिजिटल सबूतों पर केंद्रित

मामले की जांच अब डिजिटल सबूतों पर केंद्रित है। मंगलवार को पुलिस ने भोपाल कोर्ट को बताया कि घटना से जुड़े मोबाइल नंबरों की सीडीआर और टावर लोकेशन सुरक्षित रखने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को पत्र भेजे गए हैं। यह जवाब ट्विशा के परिजन के आवेदन पर पेश किया गया। आवेदन में दावा किया गया है कि मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने 46 नंबरों पर कॉल किए थे। इनमें कुछ नंबर न्यायिक अधिकारियों और जांच एजेंसियों से जुड़े लोगों के भी थे।

समर्थ बोला- ट्विशा से रिश्ता तनावपूर्ण

पूछताछ में समर्थ ने कहा कि उसका और ट्विशा का रिश्ता तनावपूर्ण था, लेकिन उसने किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा से इनकार किया। उसने माना कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन दावा किया कि यह वैवाहिक तनाव का हिस्सा था, हिंसा नहीं। समर्थ के मुताबिक, मार्च तक उनकी शादी सामान्य थी, लेकिन ट्विशा के भाई की शादी के बाद तनाव बढ़ने लगा। जांचकर्ताओं ने समर्थ से पूछा कि ट्विशा से उसकी पहली मुलाकात कैसे हुई, शादी से पहले दोनों कितने समय तक दोस्त रहे और शादी के पांच महीने के भीतर क्या बदल गया।मैं और मेरी मां बच्चा चाहते थे, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद से ही ट्विशा तनाव में रहने लगी थीं।ट्विशा के परिवार का आरोप है कि गर्भावस्था से जुड़े विवाद के बाद ही उनका मानसिक इलाज और दवाएं शुरू हुईं। इस दौरान ट्विशा का वजन लगभग 15 किलो कम हो गया था। पूछताछ का एक बड़ा हिस्सा ट्विशा की मानसिक स्थिति को लेकर रहा।

सीबीआई ने पति के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एसआईटी ने आरोपी पति समर्थ सिंह को बुधवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची। यहां सीन रिक्रिएशन किया गया।

एजी बोले-

जमानत की शर्तों का बर्बरता से उल्लंघन किया

सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एजी) प्रशांत सिंह ने कोर्ट से कहा– अदालत देख सकती है कि जमानत की शर्तों का कितनी बर्बरता से उल्लंघन किया गया। नोटिस जारी होने की तारीखें रिकॉर्ड में हैं। अदालत स्वयं उन्हें देख सकती है। तारीखों की सूची का हवाला दे रहा हूं। हम आरोपियों की तरह ट्रायल कोर्ट में अजीब सामग्री पेश नहीं कर रहे हैं। एजी ने यह भी कहा कि मैं केवल केस डायरी में मौजूद दस्तावेज को ही पढ़ रहा हूं, ताकि अदालत को सुविधा हो। इस पर आरोपी पक्ष के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा– हमने यह सामग्री नहीं देखी है। आपको हमें यह दिखाना होगा। जवाब में एजी ने कहा, आप जांच में सहयोग करेंगे, तब हर सामग्री मिल जाएगी। यह सब केस डायरी का ही हिस्सा है।

एजी प्रशांत की 5 दलीलें

- आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया- दो बार नोटिस भेजे गए, लेकिन आरोपी पक्ष ने नोटिस लेने से भी इनकार कर दिया। बाद में व्हाट्सएप पर नोटिस भेजना पड़ा।
- एफआईआर के एक घंटे में मिल गई अग्रिम जमानत- एडीजी ने कहा कि इतनी गंभीर एफआईआर दर्ज होने के सिर्फ एक घंटे के भीतर जमानत दे दी गई, जबकि जांच शुरुआती चरण में थी।
- आरोपी का रवैया 'लुका-छिपी' जैसा-एडीजी बोले कि आरोपी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं और लगातार बचने की कोशिश करती रहीं।
- प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय, जांच के लिए नहीं- आरोपी सार्वजनिक मंचों पर सक्रिय रहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जांच में सहयोग नहीं किया।
- ट्रायल कोर्ट ने गंभीर आरोप नजरअंदाज किए- ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और अभियोजन की सामग्री को नजरअंदाज कर आरोपी पक्ष के दस्तावेजों पर ज्यादा भरोसा किया।

सुप्रभात

यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर, तो वह नारी उर के भीतर,
दल पर दल खोल हृदय के अस्तर
जब बिठलाती प्रसन्न होकर
वह अमर प्रणय के शतदल पर!

मादकता जग में कहीं अगर, वह नारी अधरों में सुखकर,
क्षण में प्राणों की पीड़ा हर,
नव जीवन का दे सकती वर
वह अधरों पर धर मदिराधर।

यदि कहीं नरक है इस भू पर, तो वह भी नारी के अन्दर,
वासनावर्त में डाल प्रखर
वह अंध गर्त में चिर दुस्तर
नर को ढकेल सकती सत्वर।

- **सुमित्रानंदन पंत्र**

एसआईआर मनमाना नहीं, संवैधानिक है

सुप्रीम फैसला

- चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है, एसआईआर में 13 राज्यों में 7.41 करोड़ नाम कटे

नईदिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बुधवार को कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर-नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजा जाए। वहीं भाजपा ने विपक्ष को कहा आपके करारा झटका लगा है।

जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एसआईआर कराया गया, जबकि असम में स्पेशल रिवीजन (एसआर) हुआ।

- **अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर**– देश के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो चुका है।इनमें अब तक कुल 7.41 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।एसआईआर के पहले फेज में बिहार शामिल था।दूसरे फेज में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल था।इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान–निकोबार थे।

विपक्ष का आरोप- लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा

विपक्षी का आरोप है कि इस प्रक्रिया से लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है।विपक्ष का कहना है कि 2003 से आज तक करीब 22 साल में बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वे सारे चुनाव गलत थे।अगर चुनाव आयोग को एसआईआर करना था तो इसकी घोषणा जून के अंत में क्यों की गई। इसका निर्णय कैसे और क्यों लिया गया। अगर मान भी लिया जाए कि एसआईआर की जरूरत है तो इसे बिहार चुनाव के बाद आराम से किया जा सकता था।इतनी हड़बड़ी में इसे करने का फैसला क्यों लिया गया।

खाई में गिरा पिकअप वाहन, 3 मजदूरों की मौत

नीमच के तिलस्वा घाट पर हादसा, पेंट की बाल्टियों पर बैठे थे, शव भी रंग से सने

जावद (नप्र)। नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र के तिलस्वा घाट पर मंगलवार रात (26 मई) एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले दो दिनों में इसी घाट पर यह दूसरा बड़ा हादसा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के धौलपुर से बांसवाड़ा की ओर जा रहा पिकअप वाहन रात करीब 10 बजे तिलस्वा घाट के खतरनाक मोड़ पर बेकाबू हो गया। वाहन में पेंट की बाल्टियां लोड थीं, जिनके ऊपर मजदूर बैठे हुए थे। संतुलन बिगड़ने से वाहन सीधे खाई में जा गिरा। बाल्टियों में भरा कलर शवों पर गिरा। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

यूपी और जयपुर के रहने वाले थे मजदूर

हादसे का शिकार हुए मजदूर बरेली (उत्तर प्रदेश), गाजीपुर और राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। वे आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे। घायलों की पहचान मोहम्मद जाकिर (40), इदरीस और सोमपाल के रूप में हुई है। सिंगोली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें कोटा रेफर किया गया है।

प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा

हादसे की सूचना पर सिंगोली थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा और तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। राहगीरों की मदद से शवों को खाई से निकालकर सिंगोली अस्पताल की मॉचुरी में रखवाया गया।

अफ्रीकी देशों से अहमदाबाद आए 11 लोग आइसोलेशन में

- सरकार बोली- भारत में इबोला का कोई केस नहीं

बेंगलुरु (एजेंसी)। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस फैलने के चलते युगांडा, दक्षिण सूडान और कांगो से अहमदाबाद आए 11 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अहमदाबाद कॉर्पोरेशन के अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी ने बताया कि प्राथमिक जांच में इनमें से कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। लेकिन, एहितायन यह कदम उठाया है। वहीं, भारत सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में इबोला वायरस से जुड़ा एक भी मामला नहीं है। सरकार को यह स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि युगांडा से भारत आई एक महिला में इबोला जैसे लक्षण देखे गए थे। हालांकि बाद में महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिला 23 मई को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी। जिसके बाद उसे एहतियातन सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। महिला के शरीर में हल्का दर्द था, हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ है।अफ्रीकी देश कांगो से फैला वायरस युगांडा तक पहुंच गया है। युगांडा में इबोला के 8 मामले सामने आ चुके हैं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 28 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

आज सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं

● मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया , डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी

नई दिल्ली/बेंगलुरु(एजेंसी)। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी उनकी जगह उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीएम बना सकती है। दोनों नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ 6 घंटे तक बैठक हुई।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, बैठक में राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से सीएम पद से इस्तीफा देने का कहा और उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया। साथ ही उन्हें दिल्ली में बड़ी राष्ट्रीय भूमिका निभाने को कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समर्थकों से चर्चा के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि वे हाईकमान का फैसला मानेंगे। उन्होंने गुरुवार सुबह मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया है। इसी दिन सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं।

सीएम बोले-

शिवकुमार के नीचे काम नहीं करूंगा- सूत्रों के मुताबिक पहले सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व से कहा था कि अगर मुझे हटाया गया तो पार्टी टूटेगी, क्योंकि 50-60 विधायक मेरे साथ हटेंगे। मैं डीके शिवकुमार के नीचे काम नहीं करूंगा।

● ईरान बोला- अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट तैयार

एक महीने के भीतर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू होगी, अमेरिका नौसैनिक घेराबंदी हटाएगा

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी ने एक शुरुआती और अनौपचारिक दस्तावेज मिलने का दावा किया है, जिसमें अमेरिका-ईरान समझौते का ढांचा तैयार किया गया है।

ड्राफ्ट के अनुसार अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाएगा और नौसैनिक घेराबंदी खत्म करेगा। इसके बदले ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह व्यवस्था अमेरिकी सैन्य जहाजों पर लागू नहीं होगी। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन ईरान और ओमान मिलकर करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव

50 हजार बेटियों को फ्री स्कूटी मिलेगी

लखनऊ (एजेंसी)। योगी सरकार यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है। इस साल 50 हजार से ज्यादा मेधावी बेटियों को फ्री स्कूटी देने की तैयारी है।

सरकार 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए वादे को पूरा करने जा रही है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी तय हो चुका है।

ईवी या पेट्रोल स्कूटी? शासन में चल रहा मंथन- ईवी स्कूटी पर ज्यादा जोर : शासन का मानना है कि बेटियों को पेट्रोल स्कूटी देने से उन पर पेट्रोल का खर्च बढ़ेगा। इसके बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटी देना ज्यादा कारगर होगा। इससे वे कम खर्च में कॉलेज आ-जा सकेंगी। साथ ही परिवार पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।

टीएमसी सांसद काकोली घोष ने दिया इस्तीफा

● कहा- आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी से जुड़ी रहूंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। बारासात से सांसद घोष ने बुधवार को तृणमूल अध्यक्ष सुब्रता बख्शी को लिखे पत्र में कहा कि वह गहरे मानसिक संघर्ष और लंबे चिंतन के बाद पद छोड़ रही हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी से जुड़ी रहेंगी। काकोली सोमवार को कल्याणी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में शामिल हुई थीं। जबकि पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से अनौपचारिक रूप से मना भी किया था। पार्टी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि उनके साथ कुछ और टीएमसी नेता भी शुभेंदु की बैठक में शामिल हुए थे।

गुजरात के कच्छ से 1180 करोड़ की कोकीन जब्त

● ब्राजील से आई खेप दिल्ली भेजने की तैयारी थी; तीन विदेशी गिरफ्तार

कच्छ (गुजरात) (एजेंसी)। गुजरात में कच्छ से करीब 1180 करोड़ रुपए कीमत की 118 किलो कोकीन जब्त की गई है। इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए गए तीनों ही आरोपी विदेशी हैं।

पीएम मोदी से दिल्ली में तमिलनाडु सीएम विजय ने मुलाकात की

नईदिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की प्रधानमंत्री के साथ यह पहली औपचारिक बैठक है।

बॉयफ्रेंड भी इसी घर में रहेगा पति ने किया विरोध तो फोड़ा सिर

ग्वालियर (नप्र)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ग्वालियर एसपी की जनसुनवाई में एक पति अपनी फरियाद लेकर आया था। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई है। उसकी शादी के 18 साल हुए हैं। अब किसी से उसे प्यार हो गया है और उसकी जिद है कि उसका बॉयफ्रेंड भी इसी घर में रहेगा।

एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचा पति- दरअसल, महिला के पति का नाम राजकुमार कुशवाह है। वह ग्वालियर स्थित सिकंदर कंपू निवासी है। उसकी शादी 2008 में पूनम कुशवाह के साथ हुई थी। पति राजकुमार अपनी फरियाद लेकर ग्वालियर एसपी की जनसुनवाई में पहुंचा था। उसका कहना था कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को भी घर में रखने की जिद कर रही है।

फोड़ दिया मेरा सिर- पति का आरोप है कि इस बात का हमने विरोध किया तो उसने मेरा सिर फोड़ दिया है। शादी के बाद राजकुमार और पूनम की तीन बेटियों और एक बेटा है। उसने बताया कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य था लेकिन अब स्थिति बिगड़ रही है।

बॉयफ्रेंड को घर में रखना चाहती है पत्नी- वहीं, पीड़ित पति का आरोप है कि उसे किसी युवक से प्यार हो गया। वह शर्त रख रही है कि हम तीनों एक ही छत के नीचे रहेंगे। साथ ही कह रही है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। इसके बाद से घर में लगातार तनाव बढ़ रहा है और विवाद की स्थिति बन गई है। पुलिस ने कहा युवक की शिकायत पर जांच की जा रही है। पति ने महिला के किसी व्यक्ति के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है।

घर छोड़कर पत्नी चली गई- पति ने कहा कि विरोध करने पर उसने मेरा सिर फोड़ दिया। पांच मई 2026 को वह अपने बच्चों को लेकर घर से चली गई। इसके बाद कोई संपर्क नहीं है। साथ ही मुझे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है। घर से वह गहने और नकदी रुपए भी ले गई। साथ ही कहा है कि हत्या करवा दूंगी।

जनवरी में भी छोड़ चुकी है घर- महिला पूनम इससे पहले 22 जनवरी 2026 को भी घर छोड़कर जा चुकी है। दो महीने बाद मार्च 2026 में लौटकर आई थी। पति का आरोप है कि महिला का कमल सेन नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह उसी के साथ रह रही है।

महाराष्ट्र में पिता ने 4 बच्चों को कुएं में फेंका

फिर खुदकुशी की

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़े के बाद अपने चार बच्चों को कुएं में फेंक दिया और बाद में खुद फांसी लगा ली।

घटना जलगांव-जामोद इलाके की है। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चों की मौत हो गई। मामले की जांच जारी है और पुलिस घटना के पीछे की पूरी वजह पता लगाने में जुटी है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में होगा

नईदिल्ली (एजेंसी)। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में होगा। इस बार योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखी गई है।

25वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया गया। इस दौरान योग संगम पोर्टल, योग पार्क पोर्टल और नई योग टी-शर्ट भी लॉन्च की गई।

विजयन समर्थकों का ईडी टीम पर हमला

● पूर्व केरलम सीएम की बेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप , घर पर रेड

लाठी-पत्थर बरसाए, गाड़ी तोड़ी

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हमला किया। ईडी की 12 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के घर समेत 10 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड करने पहुंची थी। यह विजयन का किराए वाला घर है। रेड के दौरान विजयन और उनका परिवार घर में मौजूद था। जैसे ही यह खबर फैली तो विजयन के समर्थक उनके घर के बाहर जुटने लगे। दोपहर करीब 2 बजे टीम बाहर निकली तो सीपीआई कार्यकर्ताओं को विजयन के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया।

विजयन बोले-

● **ईडी की रेड से राहुल को संतुष्टि हुई होगी-** ईडी की रेड पर पिनाराई विजयन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा- काफी समय से ईडी मेरे घर की तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ लोगों को खासकर राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी। राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा था कि मेरे घर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में विपक्षी नेताओं पर हमेशा से जान-बूझकर हमले करती रही है।

कुपोषण का कलंक ?

5 साल की उम्र में हड्डियों का ढांचा बना पवन, मैहर में चल रहा इलाज, डॉक्टर बोले- जन्मजात विकृति

मैहर (नप्र)। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं को धता बताती एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। 5 साल का एक मासूम बच्चा भूख और बीमारी के कारण हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। उसके शरीर का मांस पूरी तरह सूख चुका है और पसलियां साफ दिखाई दे रही हैं। अत्यधिक कमजोरी और सूखा रोग (कुपोषण) से पीड़ित इस बच्चे को जब मंगलवार को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, तो उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत भर्ती कर लिया।

कटनी से इलाज के लिए मैहर आया परिवार- जानकारी के अनुसार, 5 वर्षीय मासूम पवन सिंह, पिता रमेश सिंह, मूल रूप से कटनी जिले की बरही तहसील के खतौली बंजारिया गांव का निवासी है। बच्चे की हालत लगातार बिगड़ने पर उसकी मां उषा सिंह और मामी संजू सिंह उसे लेकर मैहर सिविल

अस्पताल पहुंचीं। मामी संजू सिंह ने बताया कि पवन का शरीर लगातार सूखता जा रहा है, उसकी हड्डियां बाहर निकल आई हैं और शरीर टेढ़ा हो गया है। बच्चे के गले और कंधे में हमेशा तेज दर्द रहता है। कई जगह देसी-विदेशी इलाज कराने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो वे उसे मैहर लेकर आए।

विभागों में समन्वय की कमी, मासूमों पर आफत- सतना और मैहर अंचल के ग्रामीण इलाकों में लगातार सामने आ रहे कुपोषित बच्चों के मामलों के बीच मैहर में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जो पड़ोसी जिले कटनी से सामने आया है। इस घटना ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मैदानी तालमेल की पोल खोल दी है। जानकारों का कहना है कि यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और कुपोषण उन्मूलन योजनाओं की नियमित निगरानी होती, तो मासूम पवन की हालत इतनी बदतर नहीं होती।

प्रथम दृष्टया यह चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी सिंड्रोम का मामला है। -डॉ. आर.एन. पांडेय, सिविल सर्जन, मैहर

डॉ.बोले जन्मजात विकृति है मुख्य कारण

इस पूरे मामले में मैहर सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. आर.एन. पांडेय ने बताया कि बच्चे में जन्मजात शारीरिक विकृति है, जिसके कारण उसकी गर्दन टेढ़ी है और हड्डियां उभरी हुई दिख रही हैं। ऐसी विकृति वाले बच्चों में कुपोषण के लक्षण अपने आप दिखने लगते हैं। फिलहाल उसे जनरल वार्ड में भर्ती कर जांच शुरू कर दी गई है। विस्तृत पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। फिलहाल मासूम पवन डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है।

सैन फ्रांसिस्को जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट रास्ते से दिल्ली लौटी, 4 घंटे से ज्यादा हवा में रही

नईदिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहा बोइंग 777-300 ER प्लेन तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली वापस लौटा। घटना बुधवार सुबह की है। विमान में 230 यात्री-क्रू सवाल थे। एयरलाइन के मुताबिक फ्लाइट एआई-173 को सुरक्षित लैंड कराया गया। उसकी तकनीकी जांच होगी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक विमान साढ़े 4 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रहा था। उड़ान भरने के करीब 3 घंटे बाद, जब विमान चीन के हवाई क्षेत्र में था, तभी उसे वापस दिल्ली मोड़ने का फैसला लिया गया गया।

● बिहार कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर

जमीन सर्वे नियमों में बदलाव, स्वास्थ्य; प्रशासन और रोजगार सुधार पर जोर

पटना (एजेंसी)। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य और भूमि सर्वेक्षण से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में विशेष रूप से बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने, सरकारी कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा देने तथा छोटे अस्पतालों के लिए नई नियमावली लागू करने जैसे बड़े फैसले लिए गए।

● बिहार में जमीन सर्वे नियमों में होगा बड़ा बदलाव ● नए नियमों से तेजी से बनेगा खतियान और नक्शा ● विधायकों और सरकारी कर्मियों को कैशलेस इलाज ● मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, शिक्षकों की कमी होगी दूर ● छोटे अस्पतालों के लिए नई नियमावली लागू ● सड़क, सिंचाई और स्वास्थ्य परियोजनाओं को मंजूरी ● मंत्रिमंडल ने पांच स्टेट हाईवे परियोजनाओं के लिए 3744 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। ● 3744 करोड़ से बनेंगे स्टेट हाईवे

ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज

● 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस बयान को लेकर है, जिसमें 'गंदा धर्म' जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इस मामले पर ममता की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

शादी का भरोसा देकर महिला से दुष्कर्म

इंदौर। सोशल मीडिया के जरिए पहचान बढ़ाकर एक विधवा महिला को शादी का भरोसा देना और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उज्जैन निवासी आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि आरोपी लंबे समय तक शादी का झांसा देकर उसका भरोसा जीतता रहा और बाद में उसका फायदा उठाया। महिला थाना पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2020 में उसके पति का निधन हो गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान उज्जैन के एकता नगर निवासी विशाल से हुई। पहले आरोपी ने सहानुभूति जताई और मदद करने की बात कही। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने शादी का वादा करते हुए उसे सांवेर स्थित एक होटल में बुलाया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

युवक की हत्या में युवती समेत 3 को सजा

इंदौर। लूट की नीयत से युवक पर चाकू से हमला कर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में 20 वर्षीय युवती भी शामिल है। कोर्ट ने हत्या और लूट के मामले में जोया अब्बासी, अल्लू उर्फ शाहरुख और अलीम उर्फ बल्लू को दोषी माना। विशेष लोक अभियोजक सुनील मणि त्रिपाठी के मुताबिक घटना 6 अक्टूबर 2021 की है। फरियादी सतीश जाटव अपने साथी देवांशु मिश्रा के साथ दोपहिया वाहन से महालक्ष्मी नगर स्थित घर लौट रहा था। इसी दौरान पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार दो युवक और एक युवती ने उन्हें रोका और युवती को खजराना छोड़ने की बात कही। बातचीत के दौरान आरोपियों ने देवांशु के गले से चेन छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल देवांशु अगले दिन मृत मिला। पुलिस ने हत्या,लूट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। लसूड़िया पुलिस ने शिनाख्त परेड के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए,जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

बीमा कंपनी मैनेजर की अचानक मौत

इंदौर। मांगलिया इलाके में निजी बीमा कंपनी में कार्यरत मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय जितेंद्र पिता संत सिंह परिहार निवासी मांगलिया के रूप में हुई है। सोमवार रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम को जितेंद्र ने घर पर चाय पी थी। इसके बाद वह मुंह धोने के लिए गए, तभी अचानक गिर पड़े। हालत गंभीर होने पर परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जितेंद्र जबलपुर स्थित निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। वह एक सप्ताह पहले छुट्टी लेकर इंदौर अपने घर आए थे। परिवार में उनकी पत्नी, दो साल की बेटी, मां और बड़ा भाई है। पुलिस की शुरूआती जांच में हार्टअटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

हीट वेव ने भी एक जान ली

इंदौर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रिशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय गणेश पिता कन्हैया निवासी मूसाखेड़ी के रूप में हुई है। मृतक के भाई सुनील ने बताया कि रविवार से गणेश की तबीयत तेज गर्मी और हीट वेव के कारण खराब चल रही थी। सोमवार को उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गणेश अपने परिवार का मुख्य सहारा थे। परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और माता-पिता है।

सिरपुर और लिंबोदी तालाबों का निरीक्षण

इंदौर। जल संरक्षण को लेकर प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। सीएम की मंशा के अनुरूप गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर और निगम आयुक्त ने सिरपुर तालाब और लिंबोदी तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान तालाबों की जल संग्रहण क्षमता, कैचमेंट एरिया की स्थिति और बारिश का पानी लाने वाली चैनल लाइनों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्षा जल की प्राकृतिक आवक को रोकने वाले अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए, ताकि मानसून में तालाब अधिकतम भर सकें। कलेक्टर ने कहा कि तालाबों का संरक्षण जल संकट से निपटने जरूरी है। आयुक्त ने अधिकारियों को चैनल लाइनों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगम द्वारा अब तक कैलोद करताल, मोरोद माचल, निपानिया, भवरासला और रेवती रेंज सहित पांच तालाबों की चैनल सफाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। जबकि बिलावली, सिरपुर, लिंबोदी तालाब से जुड़ी अन्य चैनलों पर सफाई और बाधाएं हटाने का कार्य लगातार जारी है।

छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ

इंदौर। नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत आबकारी विभाग जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश एवं सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में मंगलवार को एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बायपास रोड मांगलिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।

सहायक आयुक्त ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि परिवार, समाज और भविष्य की खुशियों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर ही युवा जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को नशामुक्त रहने, स्वस्थ जीवन अपनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर डॉ. जीएन धड़वईकर, डॉ रवि शर्मा एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च के एनएसएस प्रोग्राम आफिसर भी ?उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अभियान की सराहना की। इसी क्रम में कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में जनजागरण अभियान संचालित किया गया।

54 दिनों में आबकारी विभाग की कार्रवाई, शराब विरोधी अभियान

इंदौर। आबकारी विभाग ने 1 अप्रैल से 24 मई तक अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशन में जिलेभर में लगातार दबिश दी गई। विभाग ने बिना किसी भेदभाव, दबाव या प्रभाव कार्रवाई की। अवैध कारोबार में शामिल तस्करों पर सख्त कदम उठाए गए। जानकारी के अनुसार, 54 दिनों के इस अभियान में कुल 1367 प्रकरण दर्ज किए गए। इस विभागीय टीम ने 3348 किलोग्राम हाथ भट्टी शराब, 2020 बल्क लीटर देशी शराब, 664 बल्क लीटर विदेशी मदिरा और 800 बियर जब्त की। इसके अलावा 31827 किलोग्राम महुआ लहान तथा 1232 किलोग्राम भांग भी बरामद की गई। जब्त मादक पदार्थों की कुल कीमत 64 लाख 11 हजार 705 रुपए आंकी गई है। वहीं अवैध शराब परिवहन में उपयोग किए जा रहे 14 दोपहिया वाहन, एक रिक्शा और एक चार पहिया वाहन भी जब्त किए गए। इन वाहनों की अनुमानित कीमत 16 लाख 14 हजार रुपए बताई गई है। आबकारी विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों के कारोबार को खत्म करने के लिए आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा। विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

हनी ट्रैप मामले में आतंकवाद विरोधी दस्ते की दस्तक, मुख्य मोबाइल जब्त

सागर के मकरोनिया इलाके में रेशू चौधरी के आवास पर छापा मारा

इंदौर। चर्चित हनी ट्रैप मामला अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की परतें खोलने के लिए अब मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी दस्ते ने भी अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। खुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए साई मनोहर के सीधे निर्देशों के बाद आतंकवाद विरोधी दस्ते को इस तफ्तीश में शामिल किया गया है। दोनों ही सुरक्षा एजेंसियां मिलकर अब इस पूरे नेटवर्क के डिजिटल पदचिह्नों और कड़ियों को जोड़ने में जुट गई हैं। संयुक्त टीम ने इस सिलसिले में सागर के मकरोनिया इलाके में स्थित रेशू चौधरी के आवास पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने उस मुख्य मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो और अन्य गोपनीय सामग्रियां अलग-अलग रसूखदार लोगों को भेजने के लिए किया जा रहा था।

डाटा पाने में जुटे विशेषज्ञ- इस बड़ी बरामदगी के बाद पुलिस उपायुक्त (अपराध) राजेश त्रिपाठी ने बताया कि तकनीकी और साइबर विशेषज्ञों की एक विशेष टीम इस जब्त मोबाइल फोन का बारीकी से अध्ययन कर रही है। विशेषज्ञ उस डाटा, संदेशों और तस्वीरों को दोबारा निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें भेजने के बाद फोन से मिटा दिया गया था या आगे बढ़ा दिया गया था। जांच एजेंसियों का मुख्य ध्यान अब इस बात पर केंद्रित है कि रेशू ने इस संवेदनशील सामग्री को किन-किन लोगों के पास भेजा था और इस खेल के पीछे कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। इस पड़ताल के दौरान रेशू के मित्र शुभम की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। छानबीन में यह बात सामने आई है कि रेशू अक्सर शुभम के साथ इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों की यात्राएं करती थी। शुभम मुख्य रूप से खेती-किसानी के काम से जुड़ा हुआ है। पुलिस को यह गहरा अंदेशा है कि शुभम को रेशू की इन संदिग्ध गतिविधियों और योजनाओं की पूरी जानकारी थी। इस आशंका के आधार पर जांच दल ने शुभम को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ भी की है।

पारिवारिक विवादों का इतिहास

जैसे-जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, मुख्य आरोपी रेशू चौधरी के जीवन से जुड़े कई चौंकाने वाले पहलू भी सामने आ रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि रेशू ने ओमान की राजधानी मस्कट में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वर्ष 2018 में उसकी शादी छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले महेंद्र नामक व्यक्ति से हुई थी। हालांकि, यह वैवाहिक रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका और महज 3 महीने के भीतर ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। विवाह टूटने के बाद रेशू ने रायपुर में अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसके अलावा जांच में यह बात भी उजागर हुई है कि रेशू का भाई स्वयं पुलिस महकमे में सेवा दे रहा है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी। पुलिस अब इन सभी पारिवारिक और पुराने कड़ियों को मौजूदा घटनाक्रम से जोड़कर देख रही है।

आरोपियों से पूछताछ की

पुलिस उपायुक्त के अनुसार, इस मामले में पकड़े गए मुख्य चेहरों से शुरुआती दौर की पूछताछ का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी और मोबाइल फोन जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पहले ही जब्त किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य संदिग्ध लोगों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां ने इस मामले में नामजद सभी 7 आरोपियों श्वेता जैन, अलका दीक्षित, जयदीप दीक्षित, लाखन चौधरी, रेशू चौधरी, जितेंद्र पुरोहित और मुख्य आरक्षक विनोद शर्मा को न्यायालय के समक्ष पेश किया। माना जा रहा है कि मोबाइल से मिलने वाले डिजिटल दस्तावेजों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।

पुलिस ने चंद घंटे में अनाज व्यापारी को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया

राऊ पुलिस की बड़ी सफलता, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

इंदौर। राऊ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के सनसनीखेज मामले का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने अपहृत अनाज व्यापारी को सुरक्षित मुक्त कराते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली गई है। मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना के मार्गदर्शन में पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, 25 मई की शाम करीब 6 बजे अनाज व्यापारी सूरज लववंशी पीथमपुर रोड स्थित वाइन शॉप के पास खड़े थे। तभी स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही व्यापारी की पत्नी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई। मामला गंभीर होने के चलते थाना प्रभारी ने राजवीर सिंह राठौर ने तत्काल विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी।

तकनीकी साक्ष्यों से सुराग

पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्ध स्विफ्ट कार की पहचान की गई। इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों की मदद से वाहन को ट्रैक करते हुए पुलिस टीम ग्राम नागपुर सांवेर पहुंची। यहां पुलिस ने घेराबंदी कर चार आरोपियों मुकेश पटेल, जितेंद्र पटेल, सुमित पटेल और गब्बर उर्फ सुनील पटेल को पकड़ा और उनके कब्जे से अपहृत व्यापारी को मुक्त करा लिया।

जमीन विवाद और लेनदेन वजह- प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि घटना के पीछे जमीन विवाद और आपसी लेनदेन का मामला था। फरियादियों की शिकायत और व्यापारी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 140(3), 115(2), 3(5) में मामला दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

कबाड़ से सजा शहर, 'वेस्ट टू वंडर' से संवरे पार्क बने आकर्षण का केंद्र

4-आर सिद्धांत पर इंदौर नगर निगम ने यह अनूठी पहल की

इंदौर। नगर निगम ने स्वच्छता के साथ नवाचार को जोड़ते हुए शहर में 'वेस्ट टू वंडर' पार्क विकसित किए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अनुपयोगी वस्तुओं का पुनः उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। नगर निगम द्वारा 4-आर सिद्धांत (रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल और रिकवर) को अपनाते हुए पुराने लोहे के स्क्रैप, टायर,पाइप, मशीनों के हिस्सों और अन्य कबाड़ सामग्री से आकर्षक कलाकृतियां तैयार की गईं। इससे शहर के विभिन्न उद्यानों को नया स्वरूप दिया गया।

नाना-नानी गार्डन, ग्लोबल गार्डन, यूरेशिया पब्लिक पार्क, केशव वाटिका और विश्राम बाग में स्थापित ये संरचनाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग इन कलाकृतियों को देखकर न केवल आनंद ले रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग का संदेश भी ग्रहण

कर रहे हैं। नगर निगम का मानना है कि यदि लोग घरों में अनुपयोगी वस्तुओं का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण अपनाएं, तो कचरे की मात्रा कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। इंदौर की यह पहल स्वच्छता, जनभागीदारी और रचनात्मक सोच का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आई है। यहां आने वाले नागरिक और पर्यटक इन कलात्मक संरचनाओं को देखकर काफी प्रभावित हो रहे हैं। 'वेस्ट टू वंडर' पार्क लोगों को यह सीख दे रहे हैं कि बेकार वस्तुओं का भी रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में इन पार्कों के प्रति खास उत्साह देखने को मिल रहा है।

बेटे-बहू ने वृद्ध दंपत्ति को निकाला, प्रशासन ने वृद्धाश्रम में रुकवाया

समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंचे लोगों की मदद की गई

इंदौर। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में व्हीलचेयर पर कलेक्ट्रेट पहुंचे दंपत्ति ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। किबे कंपाउंड क्षेत्र में रहने वाले दंपत्ति ने बताया कि उनका बेटा-बहू होटल व्यवसायी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माता-पिता को घर से निकाल दिया। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बेटे-बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद प्रशासन ने दंपती को वृद्धाश्रम में ठहरने की व्यवस्था कराई। साथ ही अधिकारियों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

ट्रैफिक सुधार के लिए अनोखी पहल- ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने प्रयास कर रहे रामचंद्र वसानी भी जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कहा सड़क किनारे खड़े वाहनों के लिए कम शुल्क वाली पार्किंग व्यवस्था लागू की जा सकती है। इससे ट्रैफिक बाधित नहीं होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने महिलाओं को भी इस योजना में प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने बताया कि वे पहले भी मेयर, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली।

कलेक्टर का सम्मान- अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद के पदाधिकारी और सदस्यों ने कलेक्टर का पगड़ी पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। परिषद अध्यक्ष सुधीर शिंदे ने कहा कि प्रशासन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के हित में सकारात्मक कार्य कर रहा है। इसी के प्रति आभार व्यक्त करने जनसुनवाई में पहुंचे थे।

जल संकट से परेशान- विस्तारा कांकड क्षेत्र के रहवासी दिलीप सेमलिया, दिनेश डोडिया ने बताया कि क्षेत्र में जल संकट बना हुआ है। इलाके में नर्मदा लाइन नहीं है, बोरिंग सूख चुके हैं और टैंकर भी नहीं पहुंच रहे। जनसुनवाई में राजेश वेद अपनी बेटी काव्या के साथ पहुंचे।

बारिश से पहले सड़कों की मरम्मत, 10 जून तक चलेगा पेचवर्क कार्य

एमआर-10, रिंग रोड, धार रोड समेत कई मार्गों पर काम शुरू

इंदौर। बारिश से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने पैचवर्क अभियान तेज कर दिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर 10 जून से पहले शहर के मुख्य और व्यस्ततम मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर सड़क सुधार कार्य किए जा रहे हैं। निगम अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा मंगलवार को एमआर-10 रोड पर हीरा नगर चौराहे से बापट चौराहे तक, राजकुमार ब्रिज, स्टार चौराहे से रेडिसन चौराहे तक, पल्हर नगर 60 फीट रोड,धार रोड तथा रिंग रोड पर मूसा खेड़ी से वर्ल्ड कप चौराहे तक पैचवर्क कार्य किया गया। कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत सुधारने के साथ गड्ढों को भरने का काम भी किया गया। निगम की कार्ययोजना के अनुसार बुधवार को भी विभिन्न प्रमुख मार्गों पर अभियान जारी रहेगा। इसमें राजकुमार ब्रिज का शेष हिस्सा,रेडिसन से स्टार चौराहा मार्ग, एमआर-10 रोड पर हीरा नगर से विजयनगर तक तथा कालानी नगर मुख्य मार्ग शामिल हैं। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों को यातायात प्रभावित न होने देने और चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रमुख सड़कों पर भी कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

विवाद और कहासुनी के बाद चले चाकू

इंदौर। तिलक नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। फरियादी विशाल सोलंकी निवासी श्रद्धा कॉलोनी ने बताया कि उसे सोमवार को नशे में धुत्त आयुष वर्मा मिला, जो गाली दे रहा था। इसी दौरान पवन भी मौके पर आ गया। कुछ देर बाद दोनों ने चाकू से हमला कर दिया। इधर, आजाद नगर इलाके में भी चाकूबाजी की घटना हुई है। पिता से कहासुनी के बाद बेटे पर चाकू से हमला कर दिया गया। अजय बछानिया की शिकायत पर पुलिस ने अनुराग निवासी पालदा चौक, शिवा और विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सोमवार रात आरोपियों की अजय के पिता रमेश से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और हमला कर दिया गया।

बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी, चालान के नाम पर उड़ाए 84 हजार

डेबिट कार्ड की जानकारी लिए बिना ही खाते से निकाली रकम

इंदौर। शहर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एमआईजी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां खुद को बैंक अधिकारी बताने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने आरटीओ चालान का हवाला देकर महिला के बैंक खाते से 84 हजार रुपए से अधिक की राशि निकाल ली।

मामले में साइबर सेल की जांच के बाद एमआईजी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 48 वर्षीय रश्मि अग्रवाल ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि 21 मई 2025 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बीओआई बैंक का अधिकारी बताया। उसने महिला से कहा कि उनकी कार का आरटीओ चालान लंबित है और उसका भुगतान डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। फोन करने वाले ने बड़ी सहजता से बातचीत करते हुए महिला से डेबिट कार्ड की जानकारी पूछना शुरू कर दिया। इस पर रश्मि अग्रवाल ने बताया कि वह कई वर्षों से डेबिट कार्ड का उपयोग नहीं कर रही हैं और उन्हें कार्ड नंबर भी याद नहीं है।

मोबाइल होल्ड पर रखवाकर ठगी

महिला के अनुसार आरोपी ने कहा कि वह बैंक रिकॉर्ड से कार्ड की जानकारी जांच कर रहा है। इसके बाद उसने मोबाइल फोन को लगभग दो मिनट तक होल्ड पर रखने के लिए कहा। कुछ देर बाद कॉल अचानक कट गया। उस समय महिला को किसी प्रकार की आशंका नहीं हुई। रात में जब उन्होंने अपने खाते का बैलेंस जांचा तो खाते से 84 हजार रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी थी। अगले दिन वह बैंक पहुंचीं और पासबुक में एंट्री कराई। वहां पता चला कि खाते में केवल 49 रुपए ही शेष बचे हैं।

अलग-अलग माध्यमों से निकासी

बैंक से मिली जानकारी के अनुसार खाते से चार से अधिक ट्रांजैक्शन किए गए थे। अलग-अलग माध्यमों और ऐप के जरिए रकम निकाली गई। ठगी की जानकारी लगते ही महिला ने तत्काल राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने यह भी बताया कि घटना के बाद उनके खाते से जुड़ा वॉट्सऐप भी डिलीट हो गया, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने मोबाइल से जुड़ी अन्य जानकारियों तक भी पहुंच बना ली थी।

संपादकीय

जनसांख्यिकी पर बड़ा फैसला

मोदी सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में अचानक आए जनसांख्यिकीय बदलाव की जांच और उसके निदान सुझाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन बड़ा और दूरगामी फैसला है। इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि यह अपने आप में गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है, जो देश का भविष्य तय करेगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा चुनाव के दौरान देश में अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पहले से मुद्दा बनाती आई है और उसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। इसी संदर्भ में केन्द्र सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए बड़ा क़दम उठाया है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भाषण में यह समिति बनाने का ऐलान किया था। अब सरकार ने इसे औपचारिक रूप से गठित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में यह समिति मामले की जाँच करेगी। पूर्व आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीपीआरएंड के पूर्व प्रमुख बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि और जनगणना आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी-1) समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति पूरे देश में अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलाव का विस्तृत अध्ययन करेगी। इस समिति का काम होगा- धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या बदलाव का पैटर्न समझना, अवैध प्रवास, अनियमित आवागमन और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कारणों की जांच, सीमा क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे बदलावों का अध्ययन,अवैध घुसपैठियों की पहचान, हिरासत और समयबद्ध तरीके से उन्हें देश से बाहर भेजने का स्थायी सिस्टम बनाने का सुझाव, सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, जनसंख्या स्थिरता और निरंतर निगरानी का प्रस्ताव,केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए नीतिगत सुझाव देना। समिति को एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। यह जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से भी बात कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। यह मुद्दा सिर्फ संप्रभुता से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संरचना और आदिवासी समाज की सुरक्षा से भी जुड़ा है। यह कड़वी सचाई है कि देश के कुछ सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी में अचानक तेजी से बदलाव हुआ है। खासकर पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में मुस्लिम आबादी असाधारण रूप से बढ़ी है। यहां तक कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के मैदानी इलाकों में भी मुस्लिम आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नजर रखना जरूरी है। वरना देश भविष्य में देश को एक और विभाजन का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि किसी धर्म विशेष अथवा समुदाय की जनसंख्या में अस्वाभाविक वृद्धि भविष्य में नए किस्म के अलगाववाद और आंतकवाद को बढ़ावा देती है। अभी यह बहुत छोटे पैमाने पर है, लेकिन जैसे जैसे जनसांख्यिकी में बदलाव आता जाएगा, वैसे वैसे अलगाव और स्वतंत्र पहचान की मांग तेज होती जाएगी। इस लिहाज से भारत तो क्या कोई भी संप्रभु देश इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकता। उधर कांग्रेस ने पैनल के अध्यक्ष जस्टिस नावलेकर की नियुक्ति को लेकर उन्हें 'भाजपाई' बताकर तंज कसा है। जस्टिस नावलेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और वहां से रिटायर होने के बाद मप्र में लोकायुक्त भी रहे हैं। लेकिन उनके सामने जो लक्ष्य है, उसे संकीर्ण सोच के बजाए व्यापक देशहित के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

अब क्या करेंगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन?

करुणानिधि चेन्नै में एक शोकसभा को संबोधित कर रहे थे। सोवियत रूस के सर्वसर्वा जोसेफ स्टालिन की चार दिन के अंतराल पर हुई मृत्यु से पिता ने पुत्र को नाम दिया स्टालिन। युवा स्टालिन की पहली जेल यात्रा हुई सन् 1976 में इमर्जेन्सी में, जब वह मीसा बंदी हुए। जेल में उन्होंने यातनाएं भी झेलीं। उन्हें बचाने के फेर में साथी चित्ति बाबू की मौत भी हो गयी। उन्होंने जेल में रहते हुए बीए किया और पहला चुनाव सन 84 चेन्नै में थाउजेंड लाइट्स से लड़ा। इसके बाद इसी इलाके से सन् 91 में पराजय को छोड़ दें तो सन् 89 में पहली जीत के बाद वह 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में अनवरत जीते। हां, यह जरूर है कि पिछले तीन चुनाव उन्होंने थाउजेंड लाइट्स के बजाय कोलथुर से लड़े। स्तालिन सन् 1982 में द्रमुक की यूथविंग के सचिव बने और करीब-चार दशक तक विंग के पदाधिकारी रहे।

नजरिया
डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

स्टालिन अब मुख्यमंत्री नहीं हैं। राजनीति की तालिका में अब वह तमिलनाडु के भूतपर्वू मुख्यमंत्री के तौर पर वर्गीकृत हैं। उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में तमिलनाडु ने विकास के मान से जबर्दस्त कुलांचे भरी। अपनी विदेश यात्राओं से उन्होंने राज्य के लिये फंड जुटाया और विकास की दर को अप्रत्याशित रूप से दहाई में ले गये। उन्होंने कांग्रेस से अपने रिश्ते को संजीदगी से निभाया। यही नहीं, उदारता और चातुर्य के चलते उन्होंने कमलहासन को राज्यसभा में पहुंचाया। पराजय को खिलाड़ी भावना से ग्रहण करनेका ही नतीजा है कि उन्होंने जनादेश को बिना किसी नुक्ताचीं के स्वीकार किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिये रैली निकाली। प्रश्न उठता है कि अब वह क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर बूझने के लिये आइये, पहले हम उनकी राजनीतिक यात्रा पर दृष्टिपात करें। वह अनीश्वरवादी हैं; नितांत नास्तिक, अलबत्ता किसी भी आस्था के प्रति उनके मन में अनादर का भाव नहीं है। वह पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हैं; लेकिन उनकी, सियासत का सलीका और लहजा अन्य सियासतदानों से भिन्न है। औरों की लकीर मिटाने के बजाय वह लंबी लकीर खींचने में यकीन रखते हैं। सरोकार उनकी राजनीति की धुरी हैं और वह लोकमंगल के जरिये राजनीतिक अभीष्ट साधने का उपक्रम करते दीखते हैं।

पूरा नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, मगर जाने जाते हैं एमकेएस या स्तालिन के नाम से! राजनीति के बीहड़ में उतरे पांच दशक से ज्यादा अर्सा हुआ। सन् 1967 में उन्होंने अपने चाचा मुरासोली मारन के लिए चुनाव प्रचार किया था। तब उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। एक मार्च सन् 24 को उन्होंने अपने जीवन के 71 वर्ष पूरे किये। राजनीति उनक रगों में है। पिता के. करुणानिधि अनेकशः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और उनके उल्लेख के बिना तमिल-राजनीति और तमिल-सिनेमा की गाथा अधूरी ही रहेगी। स्टालिन ने राजनीति में लंबी पारी खेली है। वह शरीफ मिजाज हैं और तंगजहनी से दूर हैं। वह 7 मई, 21 में मुख्यमंत्री बने। 65 लाख स्कूली बच्चों को बस्ते बांटने की महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ववर्ती सरकार मंजूरी दे चुकी थी। तैयार बस्तों पर अन्नाद्रमुक नेत्री जयललिता और पूर्व सीएम पलनीसामी की तस्वीरें छपी थीं। कोई और सीएम होता तो इन बस्तों के वितरण को रोक देता अथवा अपनी तस्वीरों के बस्ते तैयार करवाता, लेकिन स्टालिन ने उन बस्तों को बेरोक बंटवाया। इसी तरह उन्होंने सन् 21 में कोविड की दूसरी महामारी में गजब की तत्परता, साहस और प्रबंधन का परिचय दिया। उन्होंने दवाओं, एम्बुलेंसों और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 'वार रूम' शुरू किया। चिकित्सकों की चेतावनी के बावजूद जान जोखिम में डालकर वह पीपी किट पहनकर कोविड-रोगियों के वार्डों में गये और विभीषिका व उपचार की प्रत्यक्ष जानकारी लेकर जरूरी कदम उठाये। स्टालिन ने राजनीति के कीमती पाठ कुछ घर में सीखे हैं और कुछ बाहर। वस्तुतः वह घरे-बाहिरे दीक्षित योद्धा हैं। राजनीति का ककहरा उन्होंने पिता करुणानिधि और चाचा मुरासोली मारन से सीखा। उनके नामकरण का किस्सा भी दिलचस्प है। करुणानिधि चेन्नै में एक शोकसभा को संबोधित कर रहे थे। सोवियत रूस के सर्वेसर्वा जोसेफ स्टालिन की चार दिन के अंतराल पर हुई मृत्यु से पिता ने पुत्र को नाम दिया स्टालिन। युवा स्टालिन की पहली जेल यात्रा हुई सन् 1976 में इमर्जेन्सी में, जब वह मीसा बंदी हुए। जेल में उन्होंने यातनाएं भी झेलीं। उन्हें बचाने के फेर में साथी चित्ति बाबू की मौत भी हो गयी। उन्होंने जेल में रहते हुए बीए किया और पहला चुनाव सन् 84 चेन्नै में थाउजेंड लाइट्स से लड़ा। इसके बाद इसी इलाके से सन् 91 में पराजय को छोड़ दें तो सन् 89 में पहली जीत के बाद वह 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में अनवरत जीते। हां, यह जरूर है कि पिछले तीन चुनाव उन्होंने थाउजेंड लाइट्स के बजाय कोलथुर से लड़े। स्तालिन सन् 1982 में द्रमुक की यूथविंग के सचिव बने और करीब-चार दशक तक विंग के पदाधिकारी रहे। सन् 2006 में वह पहले पहल मंत्री बने और 2009-11 में प्रांत के पहले डिप्टी सीएम रहे। पेरियार जयंती को उन्होंने सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया। मंदिरों में पुजारी पद के लिये उन्होंने सभी जातियों को प्रशिक्षण की स्कीम लागू की। उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद के नामों पर गौर करें तो उनकी सोच का आभास मिलता है। एस्टर डुफ्लो, ज्यां द्रेज, रघुराम राजन, अरविन्द सुब्रमण्यम और एस. नारायण जैसे अर्थ-पंडित परिषद के सदस्य हैं। श्रीलंका के तमिल-शरणार्थियों के प्रति उनकी चिंता से सब वाकिफ हैं। वह कहते हैं कि तमिल शरणार्थी अनाथ नहीं हैं। हम उनके साथ हैं। केंटुकी ने उन्हें बिल क्लिंटन, जार्ज बुश, रोनाल्ड रीगन, मोहम्मद अली, विंस्टन चर्चिल जैसी हस्तियों के क्रम में 'सद्भावना राजदूत' से सम्मानित किया है। बिलाशक, स्टालिन भाजपा के धुर विरोधी हैं और नहीं चाहते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी मार्का राजनीति पनपे। अन्नामलै जैसे उग्र नेता के बावजूद तमिलनाड में बीजेपी की विफलता उनके लिए संतोष का विषय है। उन्होंने राजनीति के तहत विश्वासमत में द्रमुक सदस्यों को मतदान से परे रखा। उन्होंने जनादेश का हवाला देकर विपक्ष में बैठना पसंद किया। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने थलपति विजय स्टालिन के आवास पर गये। बुके का आदान-प्रदान हुआ और उत्तरीय ओढ़ाये गये। अन्नाद्रमुक का विभाजन निश्चित ही स्टालिन के पक्ष में है। स्तालिन का अपना वोट बैंक है और सरोकारों की राजनीति की छवि भी। संसद में द्रमुक महत्वपूर्ण दल है। उन्होंने संकेत दिया है कि आगामी छह माह वह थलपति-सरकार का कामकाज देखेंगे। वह यह भी चाहेंगे कि उनकी लोक लुभावन स्कीमें जारी रहें। किलाड़ी में पुरातात्विक उत्खनन में उनकी गहरी रूचि जगजाहिर है। वह चाहेंगे कि द्रविड़ सभ्यता और संस्कृति पर शोध जारी रहे। आसार यही हैं कि सत्ता गँवाने के बावजूद स्टालिन निष्क्रिय नहीं बैठेंगे और वक्त व मुद्दे का इंतजार करेंगे, जिनके बूत वह राज्य में वापसी की चेष्टा कर सकें।

काले कोट की ओट में गहराता विधिक संकट

राज्य बार काउंसिलों में स्थानीय राजनीति और भाई-भतीजावाद के कारण जाली वकीलों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र 'विधिक लोकपाल' या विशेष सतर्कता विंग की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हों। यह विंग सीधे तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो या स्थानीय पुलिस की विशेष शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संदिग्ध डिग्रियों की जांच करे।

छद्म वकील
डॉ. सुधीर कुमार
(कुरुक्षेत्र विवि में सहायक प्रोफेसर)

न्याय का मंदिर तब तक सुरक्षित और पवित्र नहीं रह सकता, जब तक उसकी देहरी पर खड़े प्रहरी स्वयं निष्कलंक न हों। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा जाली (फर्जी) वकीलों के विरुद्ध की गई तीखी और गंभीर टिप्पणी ने देश के संपूर्ण विधिक जगत और आम जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। बिना किसी प्रामाणिक विधिक योग्यता के केवल 'काला कोट' धारण कर अदालतों की गरिमा को धूमिल करने वाले ये संदिग्ध तत्व आज न्याय प्रणाली के भीतर एक परजीवी (पैरासाइट) की तरह फैल चुके हैं। जब बिना पात्रता के ऐसे तत्व स्वयं को अधिवक्ता के रूप में स्थापित करते हैं, तो वे न केवल मूक और असहाय वादियों के हितों के साथ क्रूर मजाक करते हैं, बल्कि न्याय के पावन मंदिर की नींव को भी खोखला कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह न्यायिक आत्ममंथन स्पष्ट करता है कि यह संकट महज एक प्रशासनिक शिथिलता नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक, विधिक और संवैधानिक व्यवस्था के सम्मुख उपस्थित एक अस्तित्वगत खतरा है।

इस समस्या का बारीकी से विश्लेषण किया जाए, तो यह सीधे तौर पर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की मूल भावना और उसके प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। विधिक दृष्टिकोण से यह संकट अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के नियामक ढांचे का खुला उल्लंघन है। इस अधिनियम की धारा 29 और 33 स्पष्ट करती हैं कि केवल बार काउंसिल में पंजीकृत प्रामाणिक अधिवक्ता ही न्यायालयों में पैरवी के हकदार हैं; जबकि धारा 45 के तहत अवैध वकालत के लिए केवल छह महीने के कारावास का प्रावधान है, जो वर्तमान विधिक परिदृश्य में बेहदमामूली और अप्रभावी सिद्ध हो रहा है। वास्तविक संकट तब गहराता है जब ऐसा कोई फर्जी व्यक्ति किसी नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से जुड़े संवेदनशील वादों में खड़ा होता है; यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त 'निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार' का हनन है। अयोग्य और जाली प्रतिनिधित्व के कारण अंततः 'न्याय की विफलता' सुनिश्चित होती है, जो पूरी न्यायिक संस्था की विश्वसनीयता पर ऐसा घाव देती है जिसकी भरपाई असंभव है।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव कड़ा रुख अपनाया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज (2023) के ऐतिहासिक वाद में शीर्ष अदालत ने विधिक शिक्षा के गिरते स्तर और शिथिल सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई थी। इसी तरह, 'सुधीर शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (2016)' और 'अजयशंकर श्रीवास्तव बनाम भारत संघ (2015)' के मामलों में न्यायालयों ने स्पष्ट किया कि बार से अपराधियों और जाली डिग्री धारकों को बाहर निकालना बार काउंसिल का प्राथमिक वैधानिक कर्तव्य है। इसी न्यायिक तत्परता से 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर वेरिफिकेशन (2015)' अस्तित्व में आया, ताकि हर अधिवक्ता की साख का पुनः सत्यापन हो सके। इन न्यायिक दृष्टांतों से स्पष्ट है कि न्यायपालिका इस गंदगी को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सुस्ती और इच्छाशक्ति के अभाव ने इस संकट को और गहरा कर दिया है।

वैश्विक संदर्भों में देखें तो विकसित लोकतांत्रिक देशों में विधिक साख को लेकर अत्यधिक कड़े मानक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य के 'बार एसोसिएशन' द्वारा आयोजित परीक्षा और पृष्ठभूमि की जांच इतनी त्रुटिहीन होती है कि एक छोटा सा नैतिक कदाचार भी स्थायी प्रतिबंध का कारण बन जाता है। वहीं, यूनाइटेड किंगडम में 'सॉलिसिटर्स रेगुलेशनअथॉरिटी' और 'बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड' जैसी स्वतंत्र संस्थाएं वकीलों के आचरण, उनकी निरंतर व्यावसायिक शिक्षा और डिग्रियों की डिजिटल निगरानी करती हैं। इन देशों में जाली वकालत को गंभीर धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य मानकर वर्षों के कारावास और भारी जुर्माने से दंडित किया जाता है। वैश्विक मानकों का यह तकाजा है कि भारत भी अपनी शिथिल पड़ चुकी सत्यापन प्रणाली को पूरी तरह 'री-इंजीनियर' करे, ताकि अदालतों की प्रामाणिकता और अंतरराष्ट्रीय साख अक्षुण्ण बनी रहे।

देश भर के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए एक 'केंद्रीयकृत डिजिटल विधिक डेटाबेस' का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसे सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिलों द्वारा संचालित किया जाए। इस डेटाबेस को देश के सभी विश्वविद्यालयों के डिग्री रिकॉर्ड और पहचान पत्रों से लिंक किया जाना चाहिए, ताकि न्यायालय के मुख्य द्वार पर या बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से एक क्लिक में किसी भी वकील की प्रामाणिकता की जांच की जा सके। दूसरा, प्रत्येक पांच वर्ष में अधिवक्ताओं के लिए 'अनिवार्य लाइसेंस नवीनीकरण' की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें सक्रिय वकालत का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) और अदालती कार्यवाहियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिससे केवल घर बैठे या सक्रिय न रहने वाले और संदिग्ध तत्वों को आसानी से छाँटा जा सके।

इस सुधार प्रक्रिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को केवल एक नियामक से बदलकर एक सख्त प्रवर्तन एजेंसी के रूप में तब्दील करना होगा। वर्तमान में राज्य बार काउंसिलों में स्थानीय राजनीति और भाई-भतीजावाद के कारण जाली वकीलों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र 'विधिक लोकपाल' या विशेष सतर्कता विंग की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हों। यह विंग सीधे तौर पर केंद्रीय जांचब्यूरो या स्थानीय पुलिस की विशेष शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संदिग्ध डिग्रियों की जांच करे। इसके साथ ही, देश में खुल रहे अवैध और घटिया स्तर के लॉ कॉलेजों पर तत्काल तालाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज ही जाली और अयोग्य वकीलों की इस जमात की असली नर्सरी बने हुए हैं।

इस संकट का एक अनूठा और आधुनिक आयाम 'छद्म डिजिटल सक्रियता' है। मुख्यधारा की वकालत से कटे कई अयोग्य और अप्रशिक्षित युवा आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आरटीआई एक्टिविस्ट या 'यूट्यूब वकील' बनकर कानून की अधकचरी व सनसनीखेज व्याख्या कर रहे हैं। समाज में भ्रम फैलाना, न्यायिक प्रणाली पर अनुचित दबाव बनाना और ब्लैकमेलिंग के जरिए अवैध उगाही करना इनका मुख्य जरिया बन चुका है। यह 'लीगल टेररिज्म' पारंपरिक जाली वकालत से कहीं अधिक घातक है क्योंकि यह सीधे तौर पर न्यायपालिका के प्रति जन-विश्वास को नष्ट करता है। सोशल मीडिया पर कानूनी परामर्श या विधिक व्याख्या करने वाले ऐसे तत्वों के लिए एक कड़ा और अनिवार्य 'आचार संहिता ढांचा' तैयार करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

न्यायपालिका के शीर्ष स्तर की यह चेतावनी कानूनी व्यवस्था के लिए एक अलार्म है। काला कोट केवल परिधान या रोजगार नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और संविधान के प्रति निष्ठा का पवित्र प्रतीक है। जाली वकीलों के रूप में घुसे परजीवी ईमानदार अधिवक्ताओं के श्रम का अपमान और निर्धन-अनपढ़ नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब विधिक बिरादरी, बार काउंसिल और सरकारों को एकजुट होकर इस केंचुली को फेंकना होगा और पारदर्शी, तकनीक-संचालित तथा जवाबदेह प्रणाली बनानी होगी। न्याय प्रणाली की शुद्धता बहाल किए बिना न्यायपूर्ण और सशक्त भारत की कल्पना अधूरी है। विधिक जगत के इस गौरव को वापस लाने और जन-जन के भीतर न्याय के प्रति अटूट विश्वास को जगाने के लिए अब तात्कालिक और कठोर निर्णयों का समय आ चुका है। जब कानून के रक्षक स्वयं पूर्णतः पारदर्शी और प्रामाणिक होंगे, तभी इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में 'सत्यमेव जयते' का संवैधानिक संकल्प वास्तव में चरितार्थ हो सकेगा और न्याय का मंदिर अपनी मूल पवित्रता के साथ लोक-कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मातृभाषाओं में ज्ञान का अक्षय भंडार

विचार
सुरेन्द्र दुबे
लेखक साहित्यकार और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष हैं

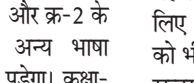

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। इसकी सभी भाषाएँ समर्थ और सशक्त है तथा संवाद के माध्यम के साथ भारतीय संस्कृति की वाहक भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा एवं भारतीय भाषा को विशेष महत्व दिया गया है। आज देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के साथ-साथ भारतीय भाषा पुनः केन्द्रीय बिन्दु बनकर उभरी है। सीबीएसई ने जो त्रिभाषा सूत्र दिया है वह आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान का अगाध स्रोत खोलने वाला है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को कक्षा 10 तक कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाएँ पढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है। इस ऐतिहासिक पहल से भारतीय भाषाओं की सामर्थ्य का उपयोग तो होगा ही साथ भारत की बहुभाषिकता को भी बल मिलेगा। इसके अन्तर्गत क्र-1 के रूप में विद्यार्थी प्रारंभ से घर की भाषा/ मातृभाषा की शिक्षा ग्रहण करेगा, क्र-2 के रूप में दूसरी भाषा (दोनों में कम से कम एक Native to India होगी) और क्र-3 के रूप में कक्षा छः से क्र-1 और क्र-2 के अतिरिक्त एक अन्य भाषा (देशी/ विदेशी) पड़ेगा। कक्षा-1 से 10 तक क्र-1, क्र-2 और क्र-3 पढ़ना होगा। यह त्रिभाषा प्रणाली सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली है। यह न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, बल्कि 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों की भावना और सुझावों को भी समाहित करती है। सीबीएसई द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र से इस प्रणाली को लागू करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भाषा विषयक अवधारणा के अनुरूप है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को किन्हीं दो भारतीय भाषाओं सहित एक अन्य भाषा (देशी/ विदेशी) पढ़ना होगा। इस निर्णय को अनावश्यक विवाद का विषय बनाना संकुचित और पूर्वाग्रहयुक्त मानसिकता का द्योतक है। इससे शिक्षा जगत में कुंडली मार कर बैठे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को चिन्ता हो रही है, क्योंकि इसका असर उनके व्यापार पर पड़ेगा। शिक्षा व्यापार नहीं है, यह भारत के भविष्य को रचने का माध्यम है जो भारतीय भाषाओं से ही संभव है। सभी भारतीय भाषाएँ परस्पर पूरक और अन्तः क्रियात्मक है और इनमें ज्ञान परंपरा की भी आवाजाही होती रही है। देश में विगत 50 वर्षों में 220 भाषाएँ लुप्त हो गई हैं और अनेक लुप्तप्राय हैं, उनमें छिपे ज्ञान के भण्डार को प्रकाश में लाना हमारा दायित्व है। अतः यह निर्णय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही भाषाओं को भी प्रासंगिक बनाने का एक सुन्दर अवसर है, अपनी भाषा में उत्कृष्ट और गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसलिए यह निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

जब-जब रुपया गिरता है, दिल बैठ जाता है

व्यंग्य
मोहम्मद हुसैन हाटपिपलीयवाला
लेखक व्यंग्यकार हैं।

हमारे मोहल्ला मे एक गजानंद नाम के व्यक्ति रहते जो सहज सरल मासूम से है हम लोग प्यार से गज्जू भाई के नाम से पुकारते है। उनका उसूल है जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ! वो बहुत सोच समझ कर चलने वालों में से है इनका छोटा परिवार सुखी परिवार है। अभी हाल ही हमारे देश के प्रधान सेवक जी ने देश के नाम संदेश मे कहा पेट्रोल गाड़ी उपयोग कम करो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करे, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा न करे, वर्क फॉर होम करे आदि कई बाते कही। हमारे गज्जू भैय्या बेहद संवेदनशील है उन्होंने प्रधानमंत्री के उद्धबोधन को अपने दिल मे उतार लिया! गज्जू भाई सबसे पहले अपनी पुरानी साइकल निकाली सर्विसिंग कराई टायर ट्यूब बदले! वो चलाने लगे उनका 80 प्रतिशत कार्य साइकिल द्वारा पूरा हो जाता है उनका जनता को संदेश ये जाता है कि इससे एक पंथ दो काज राष्ट्र भक्ति के राष्ट्र भक्ति और शरीर को स्वस्थ लाभ।

पहले वे बाज़ार मे कुछ भी स्नेक्स खा लेते थे जब से प्रधानजी का संदेश भोजन मे तेल की सीमित मात्रा का आया ये चाट वालो, होटल वालो के सामने गुजरते आंख भींच लेते है और दिल को मार लेते है मन ही मन कचौरी समोसा, पोहा,भजिए नहीं खाने का प्रण ले लेते। इसके पूर्व वे दोपहर के शाम के भोजन में सेव का उपयोग जरूर करते। अब सलाद की मात्रा ककड़ी की मात्रा बड़ा दी यहां भी उनकी देश प्रेम के साथ स्वस्थ के प्रति सजगता का पैमाना है अब धीरे धीरे स्लिम फिट हो गए है। हमारे गज्जू भाई के अंदर देश भक्ति की भावनाएं कूट कूट के भरी है! प्रधानमंत्री के बयान के बाद उनकी देश भक्ति खूब हिलोरे मार रही है वो कोई भी मौका इसे दर्शाए बिना छोड़ना नहीं चाहते। अभी विदेश जाने के लिए कुछ प्लान कर रहे थे चलो अभी पासपोर्ट तो बनाए किसी एजेंट को पासपोर्ट बनाने के लिए कहा था तभी प्रधान जी का बयान आने के बाद एजेंट को फोन कर पासपोर्ट बनाने का मना कर दिया। उनका मानना है ऐसे हालत मे विदेश यात्रा सोचना भी गुनाह है। हर देश वासियों को सहयोग करना ही चाहिए।

रही बात सोना खरीदने की तो वो सोते तो खूब है भरपूर नींद लेते है पर सोने के खरीदने की उनकी हैसियत नही है वे आर्टिफिशल ज्वेलरी से काम निकालते है हमारे गज्जू भाई को सरहद पर देश का जवान शहीद होता है तो इनकी आंखे भीग जाती है दिल खून के आंसू रोता है कि देश का जवान शहीद हो गया। देश के किसानों के लिए भी उनके दिल मे दर्द है। किसान हाड़ तोड़ मेहनत करते उनको फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता कई फसलों को लागत भी नही निकल पाती! तेल बाजार मे 200 रुपए किलो बिकता है इस हिसाब से सोयाबीन के भाव नहीं मिलते, प्याज रुला रहा है किसानों का खाद समय पर नहीं मिलता। भाव अनाप शनाप है! गज्जू भाई को सरकार की संपत्ति निजी हाथों मे सौंपना बहुत बुरा लगता है! रेलवे, एयरपोर्ट,बैंक, शिक्षा सब निजी हाथों में सौंप देंगे तो बचेगा क्या?

इस बात पर वो सरकार के खिलाफ है ! भले ही उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों न चला दे! सरकारी संपत्ति जनता के भलाई के लिए है ऐसा उनका मानना है। जब-जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है इनका दिल बैठ जाता है दिल खून के आंसू रोता है पर वो कर भी क्या सकते है! जितना इनसे बनेगा उतना ही कर पाएंगे। ये तो देश के कर्णधारों को सोचना है रूपये कैसे मजबूत हो हमसे जितना बनेगा उतना हम राष्ट्र हित मे सहयोग करेंगे। इससे ज्यादा क्या हम बच्चों की जान लोगे कहो तो वो भी देने को तैयार चाहो तो सरहद पहुंचा देना पहले ही हम दुःखी, तंग ग्रस्त है।

दृष्टिकोण

रमेश रंजन त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

ड्रेस कोड : गोलमाल है भाई सब गोलमाल है

रत्नजड़ित स्वर्णाभूषणों का प्रचलन प्रारंभ होने के बाद भी वस्त्रों की महत्ता कम नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'श्रीरामचरितमानस' में कहा है, 'बसन हीन नहिं सोह सुरारी, सब भूषन भूषित बरनारी'। अर्थात् केवल आभूषणों सेसुसज्जित सुन्दर स्त्री बिना कपड़ों के शोभित नहीं होती। परंतु समय का पहिया अजीब ढंग से घूमता है। देखिए न, आधुनिक दौर में कुछ देशों, खासकर यूरोप में, न्यूड संस्कृति के समर्थक मिल जाते हैं। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में न्यूड बीच प्रसिद्ध हैं। ऐसी धारणा है कि स्पेन में लगभग तीन सौ न्यूड बीच हैं। यह न्यूड संस्कृति विशेष रूप से पश्चिम के उन देशों में लोकप्रिय है जहां इसे प्रकृति के साथ जुड़ाव और मानवीय शांति का माध्यम माना जाता है। रिचर्ड एटनबरो की विश्व प्रसिद्ध फिल्म 'गांधी' में एक मार्मिक दृश्य है जिसमें भारत में वस्त्रों की कमी से जूझती महिला नदीमें नहाते हुए साड़ी के टुकड़े को लपेटकर बड़ी मुश्किल से अपनी लज्जा को ढंकने का प्रयास कर रही है।

हमारे चाचा जी पुराने कपड़े इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों को बाँट देते हैं। ऐसा करने के पीछे की भावना का विश्लेषण विद्वानों द्वारा किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि जिन्हें ये कपड़े मिलते हैं, साइज के न होने पर भी, वे खूब खुश होकर उन्हें पहनते हैं। पहने हुए सेकंड हैंड कपड़ों का बाजार भी होता है जिसमें कीमत बहुत कम होती है। रेडीमेड वस्त्रों के बाजार में जरा सा नुक्स होने पर माल को दोयम दर्जे का कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा खारिज किया गया फ्रेश माल सस्ती दरों पर बेचा जाता है। गरीबी के आँकड़ों के अध्ययन से अनुमान लगाया जा सकता है कि दुनिया में लगभग अस्सी-पचासी करोड़ लोगों के पास मौसम के अनुकूल पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं हैं। करोड़ों लोग चीथड़े लपेटकर गुजारा करतेहैं। नग्न रहने वाले आदिमानव धीरे-धीरे पत्ते या जानवरों की खाल लपेटने लगे। मनुष्यों को मौसम की मार से बचने के लिए शरीर को ढकने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। कालांतर में कपड़ों के साथ लोकलाज ने भी डेरा जमा लिया। मानव सभ्यता में वस्त्र धारण करना अनिवार्य मान लिया गया। रत्नजड़ित स्वर्णाभूषणों का प्रचलन प्रारंभ होने के बाद भी वस्त्रों की महत्ता कम नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'श्रीरामचरितमानस' में कहा है, 'बसन हीन नहिं सोह सुरारी, सब भूषन भूषित बरनारी'। अर्थात् केवल आभूषणों सेसुसज्जित सुन्दर स्त्री बिना कपड़ों के शोभित नहीं होती। परंतु समय का पहिया अजीब ढंग से घूमता है। देखिए न, आधुनिक दौर में कुछ देशों, खासकर यूरोप में, न्यूड संस्कृति के समर्थक मिल जाते हैं। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में न्यूड बीच प्रसिद्ध हैं। ऐसी धारणा है कि स्पेन में लगभग तीन सौ न्यूड बीच हैं। यह न्यूड संस्कृति विशेष रूप से पश्चिम के उन देशों में लोकप्रिय है जहां इसे प्रकृति के साथ जुडाव और मानवीय शांति का माध्यम माना जाता है। रिचर्ड एटनबरो की विश्व प्रसिद्ध फिल्म 'गांधी' में एक मार्मिक दृश्य है जिसमें भारत में वस्त्रों की कमी से जूझती महिला नदी में नहाते हुए साड़ी के टुकड़े को लपेटकर बड़ी मुश्किल से अपनी लज्जा को ढंकने का प्रयास कर रही है। उस गरीब महिला की बेबसी से द्रवित गांधी जी अपनी ओढ़ने वाली चादर को नदी में उसकी ओर प्रवाहित कर देते हैं जिसे वह बड़ी कृतज्ञता से लपक लेती है। शायद बापू ने इस घटना के बाद पूरे कपड़े पहनने की बजाय खादी की धोती से अपने शरीर ढंकना शुरू किया हो।

व्यक्ति के परिचय में प्रारंभिक भूमिका परिधान निभाता है। राक्षस रावण के सन्यासी रूप से सीता जी धोखा खा गई थीं। कपटी कालनेमि ने साधु बनकर बजरंगबली का रास्ता रोक लिया था। यद्यपि इनकी पोल शीघ्र ही खुल गई लेकिन वेशभूषा ने अपना असर तो दिखा ही दिया था। गणवेश से व्यक्ति के कार्यक्षेत्र की जानकारी मिल जाती है। पुलिस, डॉक्टर, वकील, सैनिक, विद्यार्थी आदि को उनकी यूनिफ़ॉर्म से पहचानना आसान हो जाता है। कपड़े का तानाबाना बुनने के लिए कपास, रेशम, जानवरों के बाल, सिंथेटिक फाइबर आदि का उपयोग सामान्य बात है। कपड़े की क़ीमत उसके कच्चे माल के दाम पर निर्भर करती है। हाथों की पूरी सफाई के साथ किए गए महीन काम वाले वस्त्र का महंगा होना लाजिमी है। यकीन न हो तो मलमल की याद कर लीजिए। संपन्नता का प्रदर्शन कपड़े भी करते हैं। वस्त्राभूषण का स्टेटस सिंबल से गहरा संबंध होता है। किस सेलिब्रिटी ने किस अवसर पर कितनी कीमती पोशाक पहनी, खबर बन जाती है। फिल्में भी इससे अछूती नहीं हैं। सूट, बूट, हैट पहनकर 'सगीना' साहब बन जाता है। 'श्री 420' का जूता भले ही जापानी, पतलून अंग्रेज़ी और सिर की टोपी रूसी लाल हो लेकिन दिल तो विशुद्ध हिंदुस्तानी होता है। मलमल की चुनरिया और लाल दुपट्टा फिल्मी हीरोइनों को बहुत पसंद है। 'देस-परदेस' में जैसा देश वैसा भेष अपनाने की सलाह देवानंद भी देते हैं। सम्मान ही नहीं, परिधान किसी को अपमानित करने का जरिया भी हो सकते हैं। पांडवों की पटरानी द्रौपदी का प्रसंग सब जानते हैं। 'महाभारत' में दुर्योधन के आदेश पर भरी सभा में दुःशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्रहरण के प्रयास को भगवान श्रीकृष्ण ने विफल कर दिया था। लोकमान्यता है कि किसी अवसर पर द्रौपदी ने कन्हैया की चोट से रिसते खून को रोकने के लिए अपनी बेशकीमती साड़ी को फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया था। श्याम सुंदर ने चीरहरण से रक्षा कर पांचाली के उस उपकार का बदला चुकाया था। इस कथा से जरूरतमंद को वस्त्रदान की महत्ता प्रतिपादित होती है।

कपड़ों की बात चली है तो बेहतरीन फिल्मकार हृषिकेश मुखर्जी की क्लासिक मूवी 'गोलमाल' में उत्पल दत्त और अमोल पालेकर के बीच हुआ रोचक वार्तालाप याद आता है। अमोल पालेकर नौकरी का इंटरव्यू देने उत्पल दत्त केसामने बैठे हैं। पालेकर अपने एक्टर मित्र देवेन वर्मा की सहायता से उधार मिले छोटे कद के कलाकार की नाप का कुर्ता पहने हुए हैं जो उनके लिए भीछोटा है। दत्त पूछते हैं कि तुम इतना छोटा कुर्ता क्यों पहनते हो? तब अमोल बहुत मज़ेदार जवाब देते हैं कि उनके 'पिता जी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरांत की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में तीस करोड़ मर्द हैं, उनमें से दस करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता छह इंच भी छोटा कर ले तो उसमें जितना भी कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है ! इसलिए पिता जी कहा करते थे कि लंबे वस्त्र पहनना बहुत हानिकारक फैशन है।' यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह फिल्म सन् 1979 में आई थी। तब हमारे देश में मर्दों की संख्या तीस करोड़ के आसपास थी। फिल्मकार का संदेश सुंदर है। खबरों में हजारों करोड़ की ड्रेस पहने अमीरों को देखकर इस बातचीत और हृषि दा' के साथ 'गोलमाल' के गाने की याद भी आ जाती है- 'गोलमाल है भाई सब गोलमाल है'।

नेहरु की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत

श्याम बोहरे

लेखक सामाजिक विज्ञान अध्येता हैं।

मानवीय गरिमा को श्रेष्ठता प्रदान करती महानता

गांधी-बोध नेहरु में गहरे तक समाया था, अनेक विषयों पर विपरीत राय रखने के बावजूद गांधी कहते थे, मेरे बाद जवाहर मेरी भाषा बोलेंगे। मैं नींद की गोद में जाऊं उसके पहले जिस प्यारे जंगल कर्मक्षेत्र की मीलों लम्बी यात्रा करना है वह, बहुत ही गहरा और लम्बा है। राबर्ट फ्रास्ट की कविता की ये पंक्तियां जो नेहरु की टेबल पर रखे नोटपेड पर लिखी थीं, वे कितना अधिक करना चाहते थे उसकी बानगी हैं। अपनी बेटी इंदिरा को जेल से लिखे गए पत्रों में दुनियाभर के अनेक कवियों से परिचित कराते हैं। प्रसिद्ध कवि अज्ञेय अपने कविता संकलन 'प्रजेंट डे एंड अदर पोयमस' की भूमिका नेहरु से लिखवाते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' की भूमिका लिखवाते हैं। भूमिका में वे लिखते हैं 'संस्कृति किसी समाज या राष्ट्र का प्रतिबिम्ब होती है यह मनुष्य के व्यवहार, सोच, नैतिक मूल्यों और जीवन शैली को आकार देती है, यह हमें पहचान, एकता और विरासत प्रदान करती है। साहित्य का अध्ययन और निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द सहित हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकारों से निकटता ने भी नेहरु के सांस्कृतिक बोध को सम्पन्न किया।

जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। बहुमुखी प्रतिभा के धनी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु को उनके सांस्कृतिक लगाव, और ज्ञान के सम्बन्ध को जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के सप्रू हाउस में आयोजित महान रुसी लेखक लिओ टालस्टाय की पचासवीं पुण्यतिथि के अवसर पर नेहरु जी ने कहा कि दो तरह की महानतायें होती हैं। एक वह जिससे साक्षातकार होने पर सामने वाला अपने आपको बहुत ही छोटा, तुच्छ, नगण्य, अस्तित्वविहीन समझने लगता है, हीन भावना से भर जाता है। दूसरे तरह की महानता होती है जिसके सामने व्यक्ति अपने आपको बड़ा समझने लगता है, वह ऊपर उठा हुआ समझता है, महान व्यक्ति के समकक्ष महसूस करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। टालस्टाय की महानता इस दूसरे किस्म की महानता थी जो मानवीय गरिमा को श्रेष्ठता प्रदान करती थी।

यह सुनते ही सभाकक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से देर तक गूंजता रहा। इसके बाद उस समय विश्व की श्रेष्ठ बौद्धिक पत्रिका एनकाउंटर के सम्पादक स्टीफन स्पेन्डर ने कहा कि एनकाउंटर के सम्पादक के नाते वे अक्सर दुनियाभर के राजनेताओं-राष्ट्रपतियों, प्रधान मंत्रियों आदि से मिलते रहते हैं। अभी टालस्टाय के सम्बंध में नेहरु ने जो कहा वह दुनिया का कोई भी राजनेता टालस्टाय के सम्बन्ध में नहीं कह सकता।

रुस के महान लेखक बोरिस पास्तरनाक को 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। रुस की सरकार उनसे नाराज थी इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार लेने के लिए स्टाकहोम जाने की अनुमति नहीं दी और बोरिस पास्तरनाक को देश निकाला देने की कार्रवाई शुरू कर दी। उस समय लन्दन में साहित्यकार आलडुअस हक्सले और एनकाउंटर के सम्पादक स्टीफन स्पेन्डर ने बोरिस पास्तरनाक को बचाने के लिए समिति बनाई। इन बुद्धिजीवियों ने जवाहर लाल नेहरु से निवेदन किया कि वे इस समिति का अध्यक्ष पद स्वीकार करें और पास्तरनाक को बचाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें। नेहरु जी ने निवेदन स्वीकार करते हुए रुस के राष्ट्रपति खुश्चेव से मांग की कि बोरिस पास्तरनाक को नोबेल पुरस्कार लेने के लिए स्टाकहोम जाने की अनुमति दें और उन्हें देश निकाला देने की कार्रवाई रोक दें। उन्हें पुरस्कार लेने के लिए स्टाकहोम तो नहीं जाने दिया, लेकिन देश निकाला देने की कार्रवाई रोक दी गई। बोरिस पास्तरनाक के बेटे ने अपनी पुस्तक में लिखा कि नेहरु के हस्तक्षेप के कारण उनके पिता को और उनके करियर को बचाया जा सका।

इसी तरह यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने जब विद्वान लेखक जिलान मस्क को जेल में बंद कर दिया था तब जवाहर लाल नेहरु ने जिलान मस्क को जेल से बाहर निकालने में भूमिका निभाई। विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता सरीखे मसलों सहित अन्य वैश्वक समस्याओं को सुलझाने में नेहरु अगुवाई करते रहे हैं।

नेहरु इस बात के जीते जागते उदाहरण जरुर थे कि मनुष्य जन साधारण के साथ आजादी के आन्दोलन में शिरकत करते हुए 3259 दिनों के कारावास के बावजूद भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगे और लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ देश को आजाद करा कर ही दम लिया। वे इसके भी उदाहरण हैं कि व्यापक और गहन अध्ययन, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों, महान व्यक्तियों, साहित्यकारों आदि का निकट सानिध्य और लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ कठोर परिश्रम आम आदमी को भी वह बना सकता है जो जवाहर लाल नेहरु थे। दो भागों में प्रकाशित 'विश्व इतिहास की झलक' उनके इतिहास और वैश्विक बोध का उदाहरण हैं। गांधी-बोध नेहरु में गहरे तक समाया था, अनेक विषयों पर विपरीत राय रखने के बावजूद गांधी कहते थे, मेरे बाद जवाहर मेरी भाषा बोलेंगे।

मैं नींद की गोद में जाऊं उसके पहले जिस प्यारे जंगल कर्मक्षेत्र की मीलों लम्बी यात्रा करना है वह, बहुत ही गहरा और लम्बा है। राबर्ट फ्रास्ट की कविता की ये पंक्तियां जो नेहरु की टेबल पर रखे नोटपेड पर लिखी थीं, वे कितना अधिक करना चाहते थे उसकी बानगी हैं। अपनी बेटी इंदिरा को जेल से लिखे गए पत्रों में दुनियाभर के अनेक कवियों से परिचित कराते हैं। प्रसिद्ध कवि अज्ञेय अपने कविता संकलन 'प्रजेंट डे एण्ड अदर पोयमस' की भूमिका नेहरु से लिखवाते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' की भूमिका लिखवाते हैं। भूमिका में वे लिखते हैं 'संस्कृति किसी समाज या राष्ट्र का प्रतिबिम्ब होती है यह मनुष्य के व्यवहार, सोच, नैतिक मूल्यों और जीवन शैली को आकार देती है, यह हमें

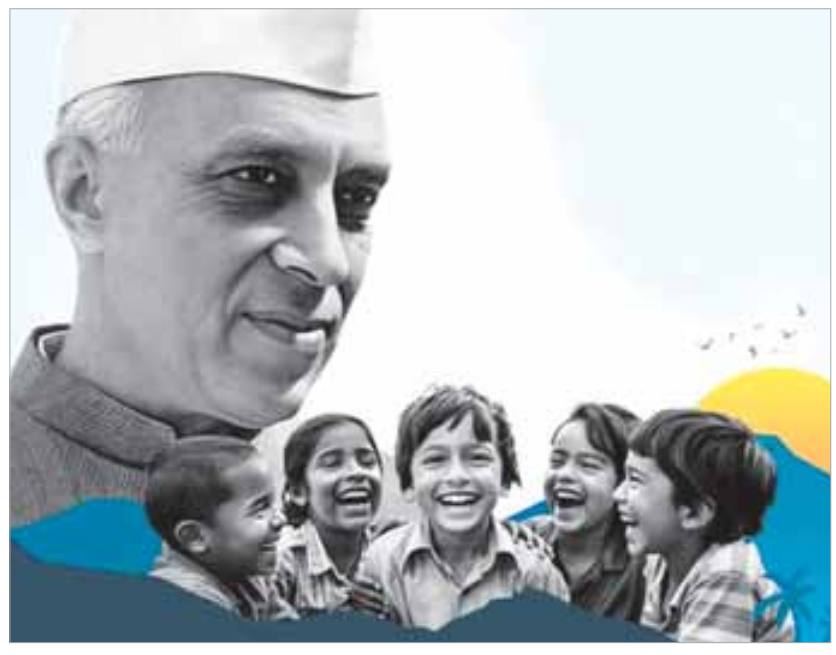

पहचान, एकता और विरासत प्रदान करती है। साहित्य का अध्ययन और निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द सहित हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकारों से निकटता ने भी नेहरु के सांस्कृतिक बोध को सम्पन्न किया।

वैज्ञानिक मानसिकता को प्रोत्साहित करने में नेहरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंसटाइन के साथ विचार विमर्श से नेहरु ने समझा कि विज्ञान और दर्शन से नई चेतना का विकास होगा। विनोबा भावे ने उन्हें विज्ञान और आध्यात्म के सम्बन्ध समझने में मदद की। 3 जून 1958 को असम के गोवाहाटी विश्वविद्यालय में नेहरु बताते हैं कि उपनिषद में खुले मन से सवाल करने की प्रवृत्ति वैज्ञानिक चेतना का लक्षण है। प्रश्न और तर्क करने की कसौटी पर परखने की बुद्ध की शिक्षा के केन्द्र में भी वैज्ञानिक मानसिकता है। इस तरह नेहरु उपनिषद और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक मानसिकता को पहचानते हैं। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन कोई आयतित पष्चिमी विचार ही नहीं वरन हमारी विरासत का भी अंग है। इस तरह नेहरु के माध्यम से हमें समझ आता है कि विज्ञान का तरीका सार्वभौमिक है। वैज्ञानिक सोच किसी भी बात को अंतिम सत्य नहीं मानता उसके लिए वह परीक्षण के लिए खुला रखता है, बात बात पर संशय करता है, प्रश्न करता है, तर्क करता है, जांच परख के बाद ही मानता है। यह प्रवृत्ति नेहरु के लेखन में बार-बार दिखती है, वे कई जगह कहते हैं, 'मुझे पूरी तरह नहीं मालूम, मुझे जो थोड़ा बहुत मालूम है, हो सकता है ऐसा न हो, यह मुझे स्पष्ट नहीं है, इस बात को समझने के लिए मेरे पास पर्याप्त अध्ययन नहीं है।' वे कहीं भी अपने आपको सर्वज्ञाता नहीं दिखाना चाहते। गंगा के सम्बन्ध कहते हैं, गंगा की तरफ देखने से मुझे हिमालय के हिम आच्छादित शिखर और गहरी घाटियों से आती हुई, जिससे मैंने बहुत प्यार किया है, याद आती है, साथ ही याद आते हैं समृद्ध दोआब के मैदान जहां मेरे जीवन की बहूमूल्य यादें बसी हैं। गंगा सुबह-सुबह सूर्य किरणों के मुलायम प्रकाश में कैसी मुस्कराती, नाचती, खेलती दिखाई देती है। लेकिन संध्या की छाया का आवरण पड़ जाने पर वही प्रवाह कैसा खिन्न और रहस्मय लगने लगता है। सर्दी के मौसम में प्रवाह खुष्क हो जाता है लेकिन गंगा मंथर शांत गति से शान से बहती रहती है। बरसात में उसका प्रचंड प्रवाह घर घर गर्जन करता हुआ विनाश का सुप्त सामर्थ्य लिए चौड़ी छाती वाले सागर में मिल जाती है और भव्य स्मारक प्रतीत होती है।

नेहरु की सम्पन्न दृष्टि साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि को टुकड़ों में नहीं वरन समग्रता में एक साथ देखती थी तभी तो वे जहां एक ओर एटामिक इनर्जी कमीशन, स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, इंडियन कांउसिल फार साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल फार एग्रीकलचर रिसर्च, आईआईटी, एम्स सरीखे विज्ञान के इदारे स्थापित कर रहे थे तो साथ साथ साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, फिल्म इंस्टीटयूट सरीखे साहित्यक-सांस्कृतिक सस्थान भी बना रहे थे। बड़े बड़े स्टील प्लांट, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भाखड़ा नंगल बांध आदि बनाकर विकास की पुख्ता और स्थाई बुनियाद भी रख रहे थे। यह याद रखना जरुरी है कि यह सब वे उस वक्त कर रहे थे जब देश के पास संसाधन अत्यंत सीमित थे। नेहरु के बाद उस स्तर और गुणवत्ता के कोई संस्थान आज तक नहीं बना पाये।

एजुकेशन

डॉ. सुदीप शुक्ल

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले पर विवाद अनुचित

भारत विविधताओं का देश है। देश के 125 करोड़ से अधिक नागरिकों के बीच भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास, भावनाओं और सामाजिक पहचान का आधार भी है। इसी बहुलतावादी स्वरूप को स्वीकार करते हुए संविधान में भारत को भाषाई विविधता के साथ एकात्मक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का मार्ग चुना गया था। इसीलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने की बात आई तो उसका मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाना, भारतीय भाषाओं को सशक्त करना तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। दुर्भाग्य से इस विषय को कुछ राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय शक्तियों ने भाषाई अस्मिता बनाम 'थोपे जाने' की बहस में परिवर्तित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। यह विवाद केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि राजनीति प्रेरित मानसिकता और कहीं न कहीं अलगाववादी सोच का भी परिचायक प्रतीत होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा फ़ॉर्मूले को लेकर एक बार फिर देश में बहस तेज हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 9 से तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य बनाए जाने संबंधी सरक्यूलर को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने नीति के अचानक क्रियान्वयन, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ, शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशासनिक अव्यवस्था जैसी चिंताएं उठाई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और मुख्य न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई के लिए सहमति भी दी है। अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की न्यायपूर्ण व्याख्या करेगा।

त्रिभाषा फ़ॉर्मूले की अवधारणा नई नहीं है और न ही यह राजनीति से प्रेरित है। कोठारी आयोग की सिफारिशों के बाद 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान किए गए थे। बहुभाषी देश होने के कारण तीन भाषाओं की शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रही है। इसका मूल स्वरूप यह था कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी तथा एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी का अध्ययन करें। इसका उद्देश्य किसी भाषा को थोपना नहीं, बल्कि भाषाई समन्वय स्थापित करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा अनिवार्य रूप से नहीं थोपी जाएगी तथा राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भाषाओं के चयन का अधिकार रहेगा। इसके बावजूद कुछ राज्यों में इसे हिंदी थोपने का अभियान बताकर राजनीतिक विरोध खड़ा किया गया।

भाषाई राजनीति का इतिहास देश में पुराना है। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी विरोध की राजनीति दशकों से क्षेत्रीय दलों के लिए राजनीतिक पूंजी का माध्यम रही है। आज भी जब त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया जाता है तो उसके पीछे शैक्षणिक तर्क कम और राजनीतिक ध्रुवीकरण अधिक दिखाई देता है। यह विडंबना ही है कि जो दल अंग्रेज़ी को सहज रूप से स्वीकार करते हैं उन्हें हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं से समस्या क्यों होने लगती है प्रश्न यह भी उठता है कि यदि एक भारतीय विद्यार्थी फ्रेंच, जर्मन या जापानी भाषा सीख सकता है तो उसे अपने ही देश की किसी अन्य भारतीय भाषा के अध्ययन से क्यों रोका जाना चाहिए

मातृभाषा किसी भी विद्यार्थी के लिए शिक्षा का सबसे सशक्त और सहज माध्यम होती है। यूनेस्को भी मातृभाषा में शिक्षा और बहुभाषा शिक्षा पर बल देता है। यूनेस्को की रिपोर्ट 'लैंग्वेजेज मैटरः ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन' के अनुसार बहुभाषी शिक्षा विद्यार्थियो की शैक्षिक पहुंच को बेहतर और व्यापक बनाती है, उनमें सीखने की क्षमता का विकास करती है जिससे परिणामों में सुधार आता है। यह सतत विकास का समर्थन करती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार प्रत्येक छात्र को तीन भाषाएं सीखनी होंगी जिनमें से दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य की गई थी जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा का चयन करने में लचीलापन प्रदान करती है। राज्य सरकारें और छात्र भाषाओं का चयन कर सकते हैं। इस नीति में कम से कम कक्षा 5 तक और यदि संभव हो तो कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल दर्शन भारतीयता को मजबूत करना है। नीति में मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्थानीय भाषाओं के संरक्षण तथा बहुभाषिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। वैज्ञानिक शोध भी यह सिद्ध करते हैं कि बहुभाषिक विद्यार्थी बौद्धिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। भाषा सीखना किसी पहचान के क्षरण का नहीं, बल्कि ज्ञान के विस्तार का माध्यम है। इसलिए त्रिभाषा फ़ॉर्मूले को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में प्रस्तुत करना वस्तुतः समाज में अनावश्यक भय पैदा करना है।

भारत जैसे विशाल राष्ट्र में भाषाई संवाद राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण आधार है। जब विभिन्न राज्यों के लोग एक-दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझेंगे तभी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना सशक्त होगी। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक शक्तियां भाषा को संवाद का माध्यम बनाने के बजाय विभाजन का हथियार बना देती हैं। क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर यदि राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी जाती है तो वह लोकतांत्रिक विमर्श नहीं बल्कि अलगाववादी मानसिकता की ओर संकेत करता है। राष्ट्र की विविधता का सम्मान आवश्यक है किंतु विविधता के नाम पर राष्ट्रीय समरसता को कमजोर करना उचित नहीं माना जा सकता। त्रिभाषा फ़ॉर्मूले का विरोध करने वाले यह तर्क देते हैं कि इससे विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा परंतु आज का युग बहुभाषिक दक्षता का युग है। नई पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से अनेक भाषाओं के संपर्क में है। ऐसे में भारतीय भाषाओं का अध्ययन विद्यार्थियों को न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करेगा बल्कि रोजगार और संवाद की दृष्टि से भी अधिक सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य किसी भाषा विशेष का प्रभुत्व स्थापित करना नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच संतुलन और सम्मान का वातावरण निर्मित करना है। भारत की भाषाई विरासत केवल हिंदी या तमिल तक सीमित नहीं है। भारत बहुभाषी देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 मुख्य भाषाएँ और 19,569 से अधिक मातृभाषाएँ (बोलियाँ) हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 38 भाषाओं को इस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की जाती रही है। संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, पंजाबी और अन्य अनेक भाषाएं भारतीय सभ्यता की धरोहर हैं। यदि विद्यार्थी विभिन्न भारतीय भाषाओं से परिचित होंगे तो उनमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय चेतना दोनों का विकास होगा। इसलिए त्रिभाषा फॉर्मूले को संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय समग्रता के साथ राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक हैं किंतु शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक स्वार्थों का माध्यम बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना है न कि भाषाई वर्चस्व स्थापित करना। आज आवश्यकता इस बात की है कि भाषा के प्रश्न को टकराव नहीं बल्कि संवाद और सहअस्तित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए। भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है और यह विविधता तभी सशक्त होगी जब भाषाएं विभाजन नहीं बल्कि एकता का माध्यम बनेंगी।

वन सुरक्षा समितियों में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा

फर्जी मजदूर एवं बिना कार्य कराए सरकारी राशि का किया गया था गबन

कार्यवाही : 5000 का इनामी फरार आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। थाना बीजादेही पुलिस ने वन सुरक्षा समितियों में हुए लाखों रुपये के गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि वन विभाग के प्रोजेक्ट अंतर्गत पदस्थ डिप्टी रेंजर एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा बिना कोई कार्य कराए, फर्जी मजदूरों एवं काल्पनिक कार्यों का उल्लेख कर शासकीय राशि विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर उसका गबन किया गया। आरोपियों द्वारा वन सुरक्षा समितियों के खातों से नियम विरुद्ध तरीके से राशि निकालकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया। 6 जनवरी 2025 को फरियादी दिनेश झारिया पिता स्व. रामदीन

झारिया (49) परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी चूनाहजूरी, रामपुर भतोड़ी परियोजना मंडल बैतूल द्वारा थाना बीजादेही में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि संभागीय प्रबंधक रामपुर भतोड़ी परियोजना मंडल बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में चूनाहजूरी परिक्षेत्र अंतर्गत संचालित 05 वन सुरक्षा समितियों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं गबन पाया गया है। जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2022 से 2023 के दौरान समिति अध्यक्षों एवं सचिवों द्वारा सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना समितियों के खातों से लाखों रुपये की राशि आहरित की गई तथा फर्जी मजदूरों एवं कूटरचित कार्य विवरण तैयार कर राशि का दुरुपयोग किया गया। प्रकरण में थाना बीजादेही में धारा 420, 406, 409, 467, 468, 470, 471, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

समितिवार गबन का विवरण

- वन सुरक्षा समिति माटीगढ़ – लगभग 24 लाख रुपये
- वन सुरक्षा समिति चिखली – लगभग 1.85 लाख रुपये
- वन सुरक्षा समिति तेंदूखेड़ा – लगभग 2.50 लाख रुपये
- वन सुरक्षा समिति आवरिया – लगभग 15.58 लाख रुपये
- वन सुरक्षा समिति काजली – लगभग 16.79 लाख रुपय

- **प्रकरण में इन्हें बनाया गया था आरोपी** – इस प्रकरण में गोविंद वासनिक, चन्द्रेश परते, ओमप्रकाश सरियाम, धनाराम यादव, प्रेमलाल सरियाम, धनाराम उइके और रम्मु कुमरे को आरोपी बनाया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी गोविंद वासनिक, चन्द्रेश परते, ओमप्रकाश सरियाम एवं धनाराम यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रकरण के शेष आरोपी प्रेमलाल सरियाम एवं रम्मु कुमरे घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहे थे।

ग्राम भजियाढाना में गोड़ी खोया पुनेम कार्यक्रम संपन्न

सोहागपुर। आदिवासी ग्राम भजियाढाना में आदिवासी समुदाय ने गोड़ी कोया पुनेम कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम एक सप्ताह तक निरंतर चलता रहा। जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं नागरिकों भाग लिया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के गणेश प्रसाद अहिरवार,उमेश उइके,श्रीउइके,सोनू कुरेची, अंकित उइके ,रोहित धुर्वे,भभूति मरकाम,मुकेश तेकाम, हाकम सल्लाम, विकाश भल्लवी, रामचरण ठाकुर नर्मदा परते,आकाश कुशराम, अभिजीत इमने, आदित्य उइके आदि ने धर्मचार रगशाह सलाम बड़ादेव का चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्र के सभी आदिवासी श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।

युवा समाजसेवी ने दी चरण पादुका

सोहागपुर। युवा समाजसेवी राहुल धौलपुरिया प्रतिवर्ष अपनी पाकिट मनी से अंश बचाकर छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, उपहार।इस साल भी चिलचिलाती धूप में खुले आसमान में जीवन यापन करने वाले नन्हे बच्चों के लिए राहत की ठंडी छांव बने युवा समाजसेवी राहुल धौलपुरिया। वर्तमान में भीषण गर्मी नागरिकों को परेशान कर रही है।ऐसे में राहुल धौलपुरिया ने नंगे पैर घूम रहे छोटे बच्चे बच्चियों चरण पादुका,कैप गमछे के अलावा परिजनों को साड़ियां प्रदान की। इस अनुकरणीय संवेदनशीलता आयोजन में उनकी बेटी कनिष्का धौलपुरिया भी साथ थीं।

तिवारी परिवार ने पुण्य तिथि पर कराया भोजन

सोहागपुर। राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर की खियाती दिन ब दिन सोहागपुर से अन्य नगरों तक जा पहुंची है। इसी तारतम्य में सोहागपुर विधानसभा के माखन नगर के तिवारी परिवार ने रेल्वे स्टेशन

परिसर में जरूरतमंद नागरिकों एवं मातृशक्ति को भोजन की व्यवस्था कराकर परिजनों के साथ परोस गिरी भी की गई। माखन नग निवासी टेक पॉइंट कंप्यूटर सेंटर संचालिका रश्मि तिवारी, आशीष तिवारी एवं अमित तिवारी ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी की चौदहवीं पुण्यतिथि के अवसर पर राम रहीम रोटी बैंक समिति के सदस्यों के साथ जरूरतमंद बेघर बेसहारा लोगों को अपने हाथों से परोसकर स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इसके अलावा तिवारी परिवार ने जरूरतमंद लोगों की आगामी भोजन व्यवस्था हेतु समिति को 21 हजार रुपये की नगद सहायता राशि भी प्रदान की । राम रहीम रोटी बैंक समिति ने तिवारी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

चेतावनी, समाधान

पंचवटी में भविष्य मालिका पुराण के माध्यम से मानव सभ्यता की रक्षार्थ थी कथा, दे गई चेतावनी, समाधान

(हीरालाल गोलानी)

सोहागपुर। पंचवटी परिसर के भोपाल कन्या स्कूल में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा एवं भविष्य मालिका पुराण कथा का आयोजन नीरजा गोलानी खूबचदानी एवं पंकज खूबचदानी ने कराया था। संपूर्ण भारत में अमूमन हर जगह श्रीमद्भागवत पुराण कथा का आयोजन सभी जगह होता है। किन्तु यहां श्रीमद्भागवत कथा के अलावा उड़िया भाषा 6 सौ साल पहले लिखी गई। भविष्य मालिका पुराण के माध्यम से मानव सभ्यता की रक्षार्थ कथा उड़ीसा के विद्वान पंडित डॉ काशीनाथ मिश्र ने उसके माध्यम से मानव प्राणी मात्र को भविष्य मालिका पुराण की चेतावनी देकर उसके समाधान का सरल उपाय बताया था। सप्त दिवसीय कथा में श्री मिश्र ने श्रीमद्भागवत कथा के प्रसंगों के अलावा भविष्य मालिका पुराण के जो तथ्य अपने मुखारविंद कहें। उसका श्रवण प्रत्येक मानव जीवन के लिए अतिआवश्यक था। उसके लिए सभी को समय अवश्य निकालना था। उड़ीसा जगन्नाथ संस्कृति के विद्वान पंडित डॉ काशीनाथ मिश्र ने सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के प्रमुख वक्ता ने उड़िया भाषा में लिखित6 सौ साल पूर्व लिखे दुर्लभ ग्रंथ को हिंदी भाषा में लिपिबद्ध करके करीबन 40 साल तक शोध करके पूरे विश्व में प्रचारित कर रहे हैं। करीबन एक सौ 56 देशों भविष्य मालिका पुराण 'पार्ट वन'2032 से सत्य युग की शुरुआत। भविष्य मालिका पुराण के आधार पर जन-समुदाय को कहा था कि आने वाला समय विश्व की मानव सभ्यता के लिए चिंतित करने वाला है। जिसमें तृतीय विश्व युद्ध की आहत तो अहम है। भविष्य मालिका में लिखा है कि जब शनि का मीन राशि में गोचर होगा एवं गुरु अतिचारी होंगे। तब इस पृथ्वी पर प्रलय जैसे हालात बनेंगे। वर्तमान में चार प्रकार की वायु विद्धमान है।आने वाले समय में 49 किस्म की विक्रत वायु चलेगी। उक्त उद्गार श्री मिश्र ने भी कथा के अवसर पर कहें थे। वहीं भविष्य मालिका पुराण के पृष्ठ 66 के क्रम 6 से 15 तक में लिखित है कि खेत की फसलों में अनाज में कीड़े लग जाएंगे। अनेक स्थानों में दुर्भिक्ष एवं अकाल पड़ेगा , वज्रपात से मनुष्य एवं जीव जन्तु,गो माता की मृत्यु होगी। पृथ्वी पर 64,प्रकार की महामारियां फैलेगी, नदियों में असमय बाढ़ आएगी, सूर्य की किरणें 10 गुना तेज हो जाएंगी। पृष्ठ 67 के क्रम 17 से30 में समुद्र में तूफान, मरूभूमि में बाढ़, भारी बरसात से मनुष्य एवं जीव जन्तुओं की मौत, भूकम्प, जंगलों में आग, चारों दिशाओं में धुआं, आंधी तूफान आदि। धरती पर चारों तरफ संकट के बादल छाएंगे। भविष्य मालिका पुराण के अध्याय 6 में क्रम 1 से 48 तक में मानवीय विक्रृति से कलयुग के अंत का संकेत दिया गया है। श्री मिश्र ने कथा में तृतीय विश्व युद्ध अवश्यंभावी बताया था। जिसमें अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल होगा जो कल्पना से भी परे हैं। दुनिया के कई शहर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। पाकिस्तान, चीन सहित करीबन 57, मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे। अमेरिका का उनका समर्थन करेगा। इस भीषण महासंग्राम में रूस खुलकर भारत का साथ देगा। बाद में फ्रांस, जर्मन एवं जापान भारत की मदद करेंगे। जापान चीन पर टूट पड़ेगा।

रिटायर्ड इंजीनियर के घर दिनदहाड़े चोरी

चोर 4 लाख की नकदी और जेवर ले गए

बैतूल/आमला। आमला थाना के बोडखी़ नाका इलाके में एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के घर दिनदहाड़े चोरी हुई। चोर घर से करीब चार लाख रुपए नकद और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित दम्मू सूर्यवंशी रेलवे से रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। वे वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बुधवार को दम्मू सूर्यवंशी और उनकी पत्नी अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, जो कनाडा में नौकरी करता है। उनकी बेटी भी उनके साथ गई थी। इसी दौरान सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया।

परिवार जब स्टेशन से वापस लौटा, तो उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर देखने पर सामान बिखरा हुआ था और अलमारियां खुली हुई थीं। अलमारी में रखे करीब चार लाख रुपए नकद और लाखों के जेवरात गायब थे। बताया जा रहा है कि घर मालिक अलमारी में ही चाबी छोड़ गए थे, जिससे चोरों को ताला तोड़ने में अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही बोडखी़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नितिन उइके मौके पर पहुंचे। आमला पुलिस ने बैतूल से डॉग स्क्वॉड और एफएसएल टीम को बुलाया। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट आबिद ने मौके से साक्ष्य जुटाए और फिंगर प्रिंट के नमूने लिए। उप निरीक्षक नितिन उइके ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आशंका है कि बदमाशों ने परिवार की पहले से रेकी की थी। परिवार के घर से निकलते ही उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने आम जनता से घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और लंबे समय के लिए बाहर जाते समय सतर्कता बरतने की अपील की है।

जल का कोई विकल्प नहीं, इसे सिर्फ सहेजा जा सकता है

कलश यात्रा, जल स्त्रोत पूजन, श्रमदान और संगोष्ठी संपन्न

बैतूल। मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर के आव्हान पर जिला समन्वयक प्रिया चौधरी के निर्देशन में प्रस्फुटन समिति नसीराबाद एवं नवांकुर सागर ग्राम उत्थान महिला एवं बाल विकास समिति द्वारा ग्राम में जल कलश यात्रा,जल स्त्रोत पूजन,श्रमदान और जल संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान ब्लॉक समन्वय राजू मांडवे के मार्गदर्शन में ब्लॉक चिचोली में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर किया गया।

जिसमें ग्राम नसीराबाद मे कलश यात्रा एवं जल संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर विकासखंड समन्वयक राजू मांडवे द्वारा जल एवं जल स्त्रोतो के संरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि जल का कोई विकल्प नहीं है इसे सिर्फ सहेजा जा सकता है और व्यर्थ व्यय नहीं करना ही समाधान है। परामर्शदाता देवेंद्र धोटे द्वारा भी जल संरक्षण को लेकर अपना व्याख्यान दिया गया। जल स्त्रोत कुएं का पूजन किया गया मेंटर मीनाक्षी वागद्रे देवेंद्र धोटे द्वारा जल कलश यात्रा का संचालन किया गया। शिव मंदिर मे जल अर्पण कर पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मीनाक्षी वागद्रे,देवेंद्र धोटे, प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष नेकराम यादव, इंद्रजीत सिंह कुशवाहा, सीएमसीएलडीपी स्टूडेंट एवं महिलाओं सहित ग्रामवासियों की सहभागिता रही।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने 'एयर एम्बुलेंस एमपी' पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ

- **एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और अधिक सरल एवं तेज गति से होगी संपन्न**

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में 'एयर एम्बुलेंस एमपी' पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत किसी भी नागरिक को समय पर उपचार के अभाव में जीवन न गंवाना पड़े। नए पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और अधिक सरल एवं तेज होगी। पोर्टल में एयर एम्बुलेंस फ्लीट की रियल टाइम ट्रैकिंग, सेवा अनुरोधों का सुगम डिजिटल प्रवाह, सेवा प्रदाताओं को तत्परता हेतु रियल टाइम नोटिफिकेशन तथा अनुमोदन प्राधिकारी को समयबद्ध स्वीकृति के लिए अलर्ट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा गंभीर एवं आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में यह सेवा अब तक 140 जीवनरक्षक मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। इनमें नवजात शिशुओं, हृदय रोग, ट्रॉमा, न्यूरोलॉजिकल आपात स्थितियों एवं अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मामलों का सफल एयर मेडिकल ट्रांसफर शामिल है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्डधारकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को निःशुल्क एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों से दूरी एवं आर्थिक स्थिति जीवनरक्षक उपचार में बाधा नहीं बने। सेवा के संचालन के लिए भोपाल में 24×7 एयर मेडिकल ऑपरेशन व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके अंतर्गत एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट बीच क्राफ्ट किंग एयर सी -90 तथा एक मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर एडबल्यू -109 लगातार स्टैंडबाय पर उपलब्ध हैं, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री अशोक बर्णवाल, आयुक्त स्वास्थ्य श्री धनराजू एस, फ्लाईओला एविएशन के सीएमडी श्री एस. राम ओला और फ्लाईओला एविएशन की डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स डॉ. मोनिका तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

धार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कल्चर सोसायटी द्वारा खिलाड़ियों को दूध एवं केले वितरित

धार। धार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कल्चर सोसायटी के तत्वाधान में आयोजित 36वें ग्रीष्मकालीन शिविर में प्रतिदिन खिलाड़ियों को विभिन्न खेल एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में क्रिकेट, कराटे, किकबॉक्सिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो, फिजिकल एक्टिविटी एवं फिटनेस ट्रेनिंग नियमित रूप से करवाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडवोकेट नंदकिशोर शर्मा एवं राजेंद्र राठौर उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों को दूध एवं केले वितरित किए गए तथा बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया।

संस्था के प्रमुख प्रदीप जोशी ने बताया कि शिविर में खिलाड़ियों के साथ कोच राम सोलंकी, विजय सोलंकी, अनुरुद्ध चावड़ा, कुलदीप राजपूत एवं डिंपल परमार लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिविर के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास एवं

खेल भावना का विकास हो रहा है। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य एवं ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए सोसायटी द्वारा प्रतिदिन पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को फिटनेस एवं खेलों के महत्व की जानकारी दी जा रही है। शिविर में विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

शासकीय आईटीआई धार में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत 9 कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों को टूलकिट वितरित

धार। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धार में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (4.0) के अंतर्गत संचालित 9 कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों के लिए गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत योजना का लाभ ले रहे प्रशिक्षणार्थियों को पीएमकेवीवाई टूलकिट के अंतर्गत टीशर्ट एवं बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम मुख्य रूप से शासकीय आईटीआई धार के प्राचार्य राहुल मंडलोई के मार्गदर्शन और गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। टूलकिट वितरण के दौरान संस्था के प्राचार्य राहुल मंडलोई ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि, 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। संस्था में युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।' ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जितेन्द्र सिंह बदनोरा ने भी छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों में उपलब्ध प्लेसमेंट के बेहतरीन अवसरों, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (2.0) की बारीकियों से अवगत कराया ताकि वे भविष्य में एक सफल करियर बना सकें। पीएमकेवीवाई किट पाकर सभी प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों पर खुशी देखी गई और उन्होंने इस कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। इस सफल आयोजन में आईटीआई धार के समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर संस्था के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जितेन्द्र सिंह बदनोरा सहित योजना से जुड़े समस्त विभागीय अधिकारी, प्रभारी एवं स्टाफ सदस्य विशेष रूप से मौजूद रहे।

आईटीआई धार के 23 प्रशिक्षणार्थियों का इप्का लैबोरेट्रीज में चयन

आईआईटी की तर्ज पर शासकीय आईटीआई धार में प्री -प्लेसमेंट ड्राइव का सफल आयोजन; 23 प्रशिक्षणार्थियों को मिले नियुक्ति पत्र

धार। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को देश की प्रतिष्ठित और धार जिले की अग्रणी फार्मास्युटिकल कंपनी इप्का लैबोरेट्रीज में रोजगार का सुनहरा अवसर मिला है। आईआईटी की तर्ज पर आयोजित इस विशेष प्लेसमेंट ड्राइव में कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा कड़े इंटरव्यू (साक्षात्कार) के माध्यम से 23 योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर संस्था के प्राचार्य राहुल मंडलोई द्वारा सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को कंपनी के नियमानुसार शुरुआत में सघन ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस ट्रेनिंग व कार्य अनुभव के आधार पर भविष्य में इन्हें कंपनी में स्थायी होने का अवसर भी प्राप्त होगा। ड्राइव के दौरान कंपनी से विशेष रूप से पधारे एचआर मैनेजर श्री गौरव शर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों को कंपनी की कार्यप्रणाली से अवगत कराया और बताया कि संस्थान में कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सभी जरूरी सुविधाएं, लाभ और बेहतर कार्य परिवेश कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा।इस पूरी वृहद प्लेसमेंट ड्राइव का कुशल समन्वय संस्था के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जितेन्द्र सिंह बदनोरा द्वारा किया गया। इस गरिमामयी और बड़े आयोजन को सफल बनाने में संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों और स्टाफ का विशेष योगदान रहा। इस ड्राइव के सफल संचालन में सतीश डोडिया, अनूप श्रृंगार, दर्शन सूर्यवंशी, प्रिया धाबोल्कर, हरिओम अहिरवार, संतोष साकेत, इनेश सोलंकी, रवि राय, सतीश विश्वकर्मा, दिनेश अहिरवार, सोलंकी, कृष्णा राजपूत सहित संस्था के समस्त प्रशिक्षण अधिकारियों का सराहनीय एवं विशेष सहयोग रहा। सभी के सम्मिलित प्रयासों से युवाओं को रोजगार दिलाने का यह अभियान पूर्णत: सफल रहा।इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्राचार्य राहुल मंडलोई, टीपीओ जितेन्द्र सिंह बदनोरा एवं समस्त स्टाफ ने चयनित सभी 23 प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल व आत्मनिर्भर भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की।

जल संरक्षण मानवता की साझा जिम्मेदारी : शिवशेखर शुक्ला

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग अंतर्गत वीर भारत न्यास द्वारा भारत भवन, भोपाल में आयोजित सदानीरा समागम 2026 के शुभारंभअवसर पर संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि यह आयोजन जल, प्रकृति और मानव सभ्यता के संबंधों पर केंद्रित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय चिंतन-यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश जल संरक्षण और जल आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। भारतीय संस्कृति में जल जीवन, चेतना और सभ्यता का आधार है तथा सदानीरा समागम परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। सात दिवसीय समागम में देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं के विशेषज्ञों के साथ नौ देशों के राजनयिक प्रतिनिधि भी सहभागी हो रहे हैं। जल, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास पर केंद्रित यह आयोजन वैश्विक सहयोग और जनभागीदारी को नई दिशा प्रदान करेगा। इस अवसर पर जेके ट्रस्ट के सीएसआर प्रमुख राम भटनागर, प्रख्यात जलविद् राजेन्द्र सिंह, हिन्दुस्तान यूनीलिवर फाउंडेशन के सीईओ डॉ. श्रमण झा, आईजीआरएमएस के डायरेक्टर डॉ. अमिताभपांडेय, आईआईएम बोधगया की डायरेक्टर डॉ. विनिता सहाय, वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी, यूनाइटेड

कॉनसियसनेस के संयोजक डॉ. विक्रांत सिंह तोमर उपस्थित थे। जलतत्व पर केन्द्रित प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रख्यात जलविद् राजेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जल को जीवन और सृष्टि के संतुलन का आधार माना गया है। जेके ट्रस्ट के सीएसआर प्रमुख राम भटनागर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कॉर्पोरेट क्षेत्र की सहभागिता से ग्रामीण अंचलों में पशुओं के स्वास्थ्य, संरक्षण और संवर्धन को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। हिन्दुस्तान यूनीलिवर फाउंडेशन के सीईओ डॉ. श्रमण झा ने कहा कि जल संरक्षण के लिए समर्पित बजट प्रावधान, जनभागीदारी, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर बल दिया। आईजीआरएमएस के डायरेक्टर डॉ. अमिताभ पांडेय ने चिंता जतायी कि आज पानी को एक प्रोडक्ट की तरह उपयोग किया जा रहा है, जिससे उसका अनियंत्रित दोहन बढ़ रहा है। आईआईएम बोधगया की डायरेक्टर डॉ. विनिता सहाय ने कहा कि भविष्य में पानी सबसे मूल्यवान करेंसी साबित होगा। इसलिए युवाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और भारतीय जीवन-मूल्यों को अपनाकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

प्रकृति को सम्मान देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता : दूसरे सत्र पृथ्वी तत्व को संबोधित करते हुए जेके सीमेंट सीएसआर प्रमुख शिल्पा जायसवाल ने कहा.कि विकास आवश्यक है, लेकिन वह प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से महिलाएँ और युवा सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को छोटे-छोटे प्रयासों से प्रकृति को कुछ लौटाने का संकल्प लेना चाहिए।

प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों की अमानत हैं: जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के सीईओ आर. पवित्र कुमार ने कहा कि मानव जीवन पंचतत्व-जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश-पर आधारित है। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्राकृतिक संसाधन वास्तव में आने वाली पीढ़ियों से लिया गया उधार हैं, इसलिए उनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ईको-टूरिज्म प्रकृति संरक्षण और आजीविका का प्रभावी माध्यम- सीईओ एल. कृष्णमूर्ति ने पर्यटन एवं ईको टूरिज्म विषय पर विचार रखते हुए कहा कि वन केवल बाघ देखने का स्थान नहीं, बल्कि जैव विविधता का जीवंत संसार हैं।

हिन्दी लेखिका संघ की ऑनलाइन गोष्ठी में जीवंत हुई लोक संस्कृति

भोपाल। 'हिन्दी लेखिका संघ, म.प्र. भोपाल' के तत्वावधान में 25 मई को गरिमामय ऑनलाइन लोक बोली कविता पाठ गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न अंचलों की लोक बोलियों की मधुर गूंज सुनाई दी, जिसमें कवयित्रियों ने अपनी आंचलिक रचनाओं के माध्यम से माटी की सुगंध और लोक संस्कृति को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मांडवी सिंह द्वारा प्रस्तुत भोजपुरी सरस्वती वंदना से हुआ। संघ की अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े ने स्वागत वक्तव्य देते हुए अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विनीता राहुरीकर ने किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश कुशवाहा 'तन्मय' ने लेखिका संघ की सृजनात्मकता और विविध विषय चयन की सराहना करते हुए अपनी रचना भी प्रस्तुत की। अध्यक्षता कर रहीं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती जनक कुमारी सिंह बघेल ने मध्यप्रदेश की लोक बोलियों की उत्पत्ति, विकास और आत्मीयता पर प्रकाश डालते हुए बघेली रचना सुनाई। गोष्ठी में बुन्देली, निमाड़ी, मालवी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, भदावरी, बघेली और अवधी बोलियों की प्रभावी प्रस्तुतियाँ हुई। बुन्देली में डॉ. संगीता भारद्वाज, श्रीमती सुनीता यादव, श्रीमती साधना श्रीवास्तव, डॉ. वंदना मिश्रा, डॉ. रेणु श्रीवास्तव, सुसंस्कृति सिंह, डॉ. मंजू मिश्रा एवं करुणा श्रीवास्तव ने काव्य पाठ किया। निमाड़ी में विभा भटोरे और डॉ. साधना गंगराड़े, मालवी में श्रीमती महिमा वर्मा एवं सरोज दवे, भोजपुरी में श्रीमती नमिता सेन गुप्ता, छत्तीसगढ़ी में डॉ. साधना शुक्ला एवं सुधा वर्मा (रायपुर), भदावरी में श्रीमती उषा चतुर्वेदी तथा अवधी में आशा सिन्हा कपूर एवं सुधा गुप्ता (जबलपुर) ने रचनाएँ प्रस्तुत कीं।पूर्व अध्यक्ष उषा जायसवाल, कुंकुम गुप्ता एवं मालती बसंत भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में

दिल्ली में 28-29 मई को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, खरीफ की तैयारी को देंगे गति

- **बीज, मौसम, बीमा, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर दो दिन चलेगा राष्ट्रीय विमर्श- शिवराज सिंह**

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 28 और 29 मई को नई दिल्ली के भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, ह्वस्ट कॉम्प्लेक्स, पूसा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जो खरीफ सीजन की तैयारी, राज्यों के साथ समन्वय और किसान-केंद्रित नीति क्रियान्वयन को नई मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बनेगा।

सम्मेलन में दलहन, तिलहन, बागवानी, बीज, प्राकृतिक खेती, जलवायु-सहिष्णु कृषि, कृषि ऋण, फसल बीमा, डिजिटल एग्रीकल्चर और राज्यों के अनुभवों पर विस्तृत विचार-विमर्श होगा। अनेक राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर खरीफ 2026 के लिए देशव्यापी तैयारी को और अधिक प्रभावी, समन्वित तथा परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28-29 मई 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खरीफ 2026 को केवल एक मौसमी अभियान के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन वृद्धि, फसल विविधीकरण, जलवायु-सहिष्णु कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसान समृद्धि से जुड़े व्यापक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में देख रही है।

संक्षिप्त समाचार

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत रायसेन में युवाओं को दिया जा रहा है 45 दिवसीय प्रशिक्षण

रायसेन (निप्र)। राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवक-युवतियों को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जिले के 87 बालक एवं 49 बालिकाओं को माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गत दिवस डीएसपी श्री अनुराग राजपूत तथा सूबेदार नीतू ठाकुर द्वारा प्रशिक्षण स्थल शासकीय कन्या शिक्षा परिसर के सभागार में सभी प्रतिभागियों को पुलिस एवं सुरक्षा बल में भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डीएसपी श्री राजपूत ने अपने उद्बोधन में अनुशासन, नैतिक मूल्य, ईमानदारी की महत्ता बताते हुए प्रशिक्षण के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पूर्ण उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त कर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर की अधीक्षिका श्रीमती लक्ष्मी परिहार भी उपस्थित रहीं।

सीहोर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में निशुल्क प्रवेश प्रारंभ

सीहोर (निप्र)। सीहोर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्राऐं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग ब्रांच अथवा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट ब्रांच में प्रवेश ले सकती है। प्राचार्य डॉ. प्रमोद शर्मा ने बताया कि प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया बेवसाईट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। छात्राओं को सर्वप्रथम 29 मई से पहले डॉ बाबा साहब अंबेडकर योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अपना पंजीयन कराना होगा एवं 15 से 02 जून के बीच ऑनलाईन ही कॉलेज के लिए च्वाईस फिलिंग करनी होगी। इसके साथ ही प्रवेश के लिए संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ 08 से 13 जून के बीच उपस्थित होना होगा। छात्राओं को यदि एमपी ऑनलाईन कियोस्क से पंजीयन संबंधी कोई भी समस्या आती है तो छात्राऐं सीधे संस्था में आकर भी अपना पंजीयन करा सकती है। संस्था में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है, साथ ही छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। संस्था से सभी छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें और स्टेशनरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा जिन छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक होगी उन्हें प्रतिमाह 1000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ग्राम वर्धा में जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण, अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

विदिशा (निप्र)। जनगणना-2027 के अंतर्गत जिले में संचालित जनगणना कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने हेतु जिला कार्यालय से जनगणना पर्यवेक्षक सुश्री दीक्षा केसरवानी एवं तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल द्वारा ग्राम वर्धा में जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जनगणना कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं परिवार संबंधी आंकड़ों के संकलन कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार जानकारी दर्ज किए जाने , रिकॉर्ड संधारण तथा कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मेरा युवा भारत रायसेन द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं प्रसारण प्रणाली पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायसेन (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत रायसेन द्वारा युवाओं के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं प्रसारण प्रणाली विषय पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी तथा जनसंचार के विभिन्न आयामों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में रायसेन जिले के रेडियो स्टेशन रेडियो सेहर 89.6 के संचालक श्री विपिन यादव द्वारा प्रतिभागियों को रेडियो स्टूडियो की कार्यप्रणाली, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, कैमरा संचालन, मल्टीमीडिया उपकरणों के उपयोग एवं प्रसारण तकनीकों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। युवाओं ने स्टूडियो विजिट के माध्यम से यह समझा कि समाचार, जनहित संदेश एवं विभिन्न कार्यक्रम किस प्रकार तैयार होकर जनता तक पहुँचते हैं।इस अवसर पर युवाओं को जनसंचार कौशल के महत्व के

बारे में भी जानकारी दी गई। श्री सचिन यादव ने बताया कि वर्तमान डिजिटल एवं तकनीकी युग में मीडिया, संचार एवं मल्टीमीडिया तकनीक से जुड़े कौशल युवाओं के व्यक्तित्व विकास, रोजगार एवं सामाजिक जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों में संचार क्षमता, प्रस्तुतीकरण कौशल, टीमवर्क एवं तकनीकी समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। युवाओं ने इस अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

मां नर्मदा पूजन, कलश यात्रा और जल संरक्षण शपथ के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम

जल है जीवन का आधार, संरक्षण में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी : प्रभारी मंत्री गौर

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान बना जनआंदोलन : प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर

सीहोर (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर सीहोर जिले के नर्मदा आंवलीघाट पर जिला स्तरीय जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि जल सृष्टि का आधार है और बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल ही जीवन को संतुलन और समृद्धि प्रदान करता है। यदि आज जल संरक्षण के प्रति गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल

संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। गांव तथा नगरों में नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं और पोखरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन आंदोलन बन गया है और इसके सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण एवं जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल को अधिक से अधिक रोककर धरती के भीतर पहुंचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही अधिकाधिक वृक्षारोपण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है और सामूहिक सहभागिता से ही इस दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुड़ी पड़वा से प्रारंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक संचालित किया जा रहा है। इस अवधि में सीहोर जिले में अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए आम नागरिकों को व्यापक रूप से जोड़ा गया है तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। कार्यक्रम के आरंभ में प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने मां नर्मदा की पूजा-अर्चना की तथा कलश यात्रा में शामिल हुईं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उन्होंने उपस्थित नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री राजेंद्र सिंह राजपूत तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जन यादव ने भी संबोधित किया।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 486 गर्भवती महिलाओं की जांच, 233 हाई रिस्क मिली

बैतूल (निप्र)। गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 एवं 25 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि सोमवार को जिले में आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 486 गर्भवती महिलाओं की जाचं एवं 233 हाई रिस्क चिन्हित, 52 सोनोग्राफी की गईं। शिविर में सभी महिलाओं की खून की जांच एवं जीडीएम की जांच की गई। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय बैतूल में आयोजित शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ वंदना धाकड़ द्वारा 76 गर्भवती महिलाओ की चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें 16 गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क के रूप में चिन्हित किया गया, वहीं 52 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई। सिविल अस्पताल आमला में महिला चिकित्सा अधिकारी डॉ ईवान जेम्स द्वारा 34 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें हाई रिस्क 15 महिला पायी गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोड़ाडोंगरी में स्त्री रोग चिकित्सक (पीजीएमओ) डॉ कविता कोरी द्वारा 51 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 36 हाई रिस्क महिलाओं की जांच की गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही में डॉ व्योमा वर्मा एवं डॉ रेशमा खान द्वारा 18 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 15 हाई रिस्क महिलाएं पायीं गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुलताई में स्त्री रोग चिकित्सक डॉ सरिता कालभोर द्वारा 44 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 29 हाई रिस्क महिलाएं पाई गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिचोली में चिकित्सा अधिकारी डॉ राहुल देशमुख 35 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें हाई रिस्क 24 महिलाएं पायी गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेहरा में चिकित्सा अधिकारी डॉ नीलम महाजन 86 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 13 हाई रिस्क महिलाऐं हाई रिस्क पायी गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आठनेर में डॉ प्रीति नरवरे द्वारा 35 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 15 हाई रिस्क महिलाएं पायीं गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉ सोनू गोंड द्वारा 50 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 45 हाई रिस्क महिलाएं पायीं गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमपुर में डॉ क्षितिज पचौली द्वारा 32 गर्भवती महिलाओं की जांच जिसमें 13 हाई रिस्क महिलाएं पायीं गईं।

जिले के सभी स्कूलों के 500 मीटर क्षेत्र को बनाया जाए नो-ड्रग जोन

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम तथा बेहतर समन्वय के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा मुक्ति एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों के 500 मीटर क्षेत्र को नो-ड्रग जोन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में ड्रग्स, स्मैक एवं आर्टिफिशियल नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने बताया कि गत वर्ष चोपना एवं रानीपुर क्षेत्र में अफीम की खेती के प्रकरण में मंदसौर एवं नीमच से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कृषि, वन एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि नशीले पदार्थों की अवैध खेती से संबंधित जानकारी तत्काल पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और आत्मनिर्भर खेती के लिए किया गया जागरूक

कृषि रथ के समापन दिवस पर नटेरन में वृहद कृषक संगोष्ठियां आयोजित

विदिशा (निप्र)। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में संचालित कृषि रथ अभियान के समापन दिवस पर विकासखंड नटेरन के ग्राम एंचदा, खड़ेर एवं जोगी किरोंदा में वृहद कृषि कल्याण शिविर एवं कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में आयोजित इन शिविरों में कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न योजनाओं, तकनीकों एवं शासन की प्राथमिकताओं की जानकारी प्रदान की। शिविर में कृषि अभियांत्रिकी विभाग से एम.पी. स्टेट एग्रो के जिलाधिकारी श्री मनोहर उईके सहित कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों तक शासन की योजनाओं की

जानकारी पहुंचाना, कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना तथा किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को गति देना रहा। योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर जोर शिविर के दौरान अधिकारियों ने किसानों को कृषि एवं संबद्ध विभागों की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने किसानों से समय पर पंजीयन कराने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आग्रह किया। साथ ही मैदानी अमले को भी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में किसानों की समस्याएं भी गंभीरता से सुनी गईं और संबंधित विभागों द्वारा उनके निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। किसानों को उन्नत खेती, फसल प्रबंधन एवं कृषि संसाधनों के बेहतर उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई। कृषक कल्याण वर्ष के उद्देश्य बताए गए विकासखंड तकनीकी प्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय किसानों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने, उन्नत बीजों के उपयोग, आधुनिक तकनीकों को अपनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, फसल बीमा तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाकर खेती की लागत कम करना और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही जानकारी क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी श्री अभिषेक जैन ने बताया कि कृषि, पशुपालन एवं अन्य संबद्ध विभागों के समन्वय से विशेष शिविर, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राइट क्लिक

जिस नतीजे पर परीक्षार्थियों को ही भरोसा न हो, उसका क्या औचित्य है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

देश में मेडिकल में प्रवेश के लिए 'नीट' परीक्षा में पेपर लीक का विवाद थमा भी नहीं था कि अब सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। जिस भारी संख्या में असंतुष्ट परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन, स्कैन कॉपी और मार्क्स वेरीफिकेशन की मांग कर रहे हैं, उससे तो इस परीक्षा की प्रमाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। परीक्षार्थियों के अलावा उनके अभिभावक भी परेशान हैं। नतीजों में गड़बड़ी का यह सबसे बड़ा घोटाला होता दिख रहा है। क्योंकि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में देश भर के 17 लाख 68 हजार परीक्षार्थी बैठे थे। इनमें से 4 लाख से ज्यादा यानी एक चौथाई परीक्षार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और मार्किंग पर संदेह जताते हुए पुनर्मूल्यांकन और स्कैन कॉपी की मांग की है। हालांकि रिवेल्युएशन के आवेदन आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होती है। इस बार तो उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग में गड़बड़ी और गलत कॉपी स्कैनिंग ने लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। जिनके मार्क्स अपेक्षा से बहुत कम आए हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। शिकायतों का आलम यह है कि सीबीएसई का पोर्टल बार-बार क्रैश हो रहा है।

शिकायतकर्ता परीक्षार्थियों का कहना है कि कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के कारण उनके नंबर अपेक्षा से बहुत कम आए हैं। दरअसल ओएसएम एक डिजिटल इवैल्यूएशन प्रोसेस है। इसमें कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया जाता है। सबसे पहले आंसर शीट को हाई-स्पीड स्कैनर से स्कैन किया जाता है फिर डिजिटल फॉर्मेट यानी पीडीएफ अथवा इमेज में बदला जाता है। स्कैन्ड कॉपियों को सिक्योर सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाता है। कॉपी चेक करने वाले टीचर लैपटॉप या टैबलेट पर लॉगिन करके स्क्रीन पर ही आंसर देखते हैं और डिजिटल पेन या माउस से मार्क्स देते हैं। सिस्टम खुद ही मार्क्स जोड़ता है और दावा है कि इसमें टोटलिंग एरर नहीं होता। बताया जाता है कि ऑनलाइन कॉपी जांचने वाले कई शिक्षकों ने स्कैन की गई आंसर शीट्स के ब्लर (अस्पष्ट) होने और तकनीकी समस्याओं को लेकर शिकायतें की थीं। लगता है कि ब्लर कॉपियों को पढ़े बिना ही अंदाज से नंबर दे दिए गए। नुकसान मेधावी विद्यार्थियों का हो गया। परीक्षार्थियों ने बड़े पैमाने पर भुगतान संबंधी दिक्कतों, धुंधली स्कैन कॉपियों, गायब पन्नों और यहां तक कि गलत उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड होने जैसी समस्याओं की शिकायत की है। हालांकि सीबीएसई का दावा है कि ओएसएम तकनीक पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उससे कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यह कि जब कॉपी की डिजीटल चेकिंग की व्यवस्था की विश्वसनीयता पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाती, तब इसे इतनी जल्दबाजी में लागू करने का मकसद क्या था? शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो, इसमें दो राय नहीं, लेकिन नई व्यवस्था लागू करने के पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेने की जिम्मेदारी किसकी है? और यह व्यवस्था सीधे 12 बोर्ड में लागू करने का तुगलकी निर्णय लेने का क्या मतलब है? यह सिस्टम भी परीक्षा के एक महीने पहले ही लागू किया गया। समझदारी तो इसी में थी कि पहले इसे पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर किसी एक झोन में बिना बोर्ड परीक्षा वाली किसी क्लास की लोकल परीक्षा में लागू कर इसकी खामियों को समझकर उन्हें दूर किया जाता और फिर धीरे-धीरे उसे समूची बोर्ड परीक्षा में लागू किया जाता।

हैरानी की बात तो यह है कि वेदांत श्रीवास्तव जैसे 12वीं के परीक्षार्थी ने अपनी स्कैन कॉपी ही गलत बताई और सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली तो भी उसे सोशल मीडिया में 'पाकिस्तानी' कह कर ट्रोल किया गया। इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से 12 बोर्ड की उत्तीर्ण दर में 3.19 प्रतिशत की गिरावट आई है।

गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा में 12वीं बोर्ड परीक्षाएं बच्चों के भविष्य की दिशा और नींव तैयार करती हैं। अगर उसी में भारी धांधली हो और उस धांधली का घुमा-फिराकर बचाव किया जाए तो लोग किस पर भरोसा करें ? भारत में अभी तक हाथ से लिखी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षकों द्वारा मैनुअली जांचने की ही परंपरा रही है। खामियां उसमें भी रही हैं, फिर भी तुलनात्मक रूप से यह व्यवस्था सर्वमान्य रही है, क्योंकि उसमें मनुष्य का विवेक केन्द्र में रहता है। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की तेजी से, ज्यादा तकनीकी और कथित रूप से पारदर्शी तरीके से कराने के नाम पर जो कुछ किया है, उससे तो पूरे सिस्टम की प्रमाणिकता और निष्पक्षता पर ही सवालों के घेरे में है। शिक्षा प्रणाली में बदलते जमाने के हिसाब से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आज दुनिया के सौ देशों में डिजीटल वेल्युएशन सिस्टम लागू है। लेकिन उसे लागू करते समय पूरी सावधानियां बरती जाती हैं और उसे फुलप्रूफ बनाया जाता है। लेकिन लगता है कि सीबीएसई ने इसे तुगलकी अंदाज में और वो भी सीधे और 12वीं बोर्ड जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा में लागू कर दिया। जबकि केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षक संघों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि नए सिस्टम को लेकर शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। नई व्यवस्था को हडबड़ी में लागू करने का नतीजा है कि इस बार सीबीएसई की 98 लाख 60 हजार उत्तर पुस्तिकाओं में से 11 लाख 31 हजार कॉपियों के मार्क्स वेरिफिकेशन के आवेदन आ चुके हैं। यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। जिस नतीजे पर परीक्षार्थी को ही भरोसा नहीं है, उसका क्या औचित्य है? सीबीएसई नतीजों पर मचे देशव्यापी बवाल के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इसे गंभीरता से लेते हुए ओएमएस सिस्टम की प्रामाणिकता की जांच आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों से कराने की घोषणा की है, लेकिन जिन बच्चों का नुकसान हो गया है, उनका क्या? व्यवस्था को सुधारने, तेज और पारदर्शी बनाने के नाम पर सीबीएसई ने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका जिम्मेदार कौन है?

समीक्षा

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा की।

पीएम सूर्य घर योजना

39 हजार 975 उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 311 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

भोपाल (नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रान्तर्गत आने 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 39 हजार 975 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। इनके खातों में 311 करोड़ 64 लाख से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में जमा कराई जा चुकी है। कंपनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं।

गौरतलब है कि इस योजना में एक किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 30 हजार रूपये, दो किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा तीन किलोवॉट या उससे अधिक के सोलर संयन्त्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

कहां करें आवेदन- पीएम सूर्यघर योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था। योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके लिए पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय ऐप, वॉट्स ऐप चेटबॉट व टोल फ्री नं, 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम तथा बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए।

गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2024 से स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं, जो कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एस.ओ.आर. रेट पर उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं द्वारा सोलर वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में लगभग 6 से 8 हजार रूपये तक की कमी परिलक्षित हो रही है।

लगा करियर खत्म हो रहा

...तब मोदी का फोन आया

पीएम ने कहा- सीएम नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं, 'अपनापन' किताब के 10 किस्से

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 साल के अनुभवों पर एक किताब लिखी है। 'अपनापन : नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव' नाम की किताब का विमोचन दिल्ली में मंगलवार (26 मई) को पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किया।

शिवराज की इस किताब में कई चौंकाने वाली बातें हैं। एक किस्सा 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त का है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर को लेकर विपक्ष तेजी से मुद्दा बना रहा था।

इस बीच पीएम मोदी का उनके पास कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। इस किताब में शिवराज ने पहलगाम हमला, कोरोना काल, 1990 के दशक की कई बातों को शामिल किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम, संगठन के प्रति निष्ठा और अपने अनुभवों को खासतौर पर बताया है।

जब शिवराज को आया पीएम मोदी का फोन

शिवराज लिखते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की पहली सूची जारी हुई, लेकिन उसमें शिवराज सिंह चौहान का

नाम नहीं था। इसी बीच उनके एक भाषण की लाइन- यदि हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे को विपक्ष ने इस तरह प्रचारित करना शुरू कर दिया, मानो उनका राजनीतिक अंत तय हो चुका हो।

कांग्रेस नेताओं ने 'मामाजी का श्राद्ध' जैसे तंज कसने शुरू कर दिए। माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि शिवराज का दौर खत्म हो गया। इसी तनावपूर्ण माहौल में नरेंद्र मोदी का फोन आया।

किताब में शिवराज लिखते हैं कि मोदी ने बातचीत की शुरुआत ही इस वाक्य से की..मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा, मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने राजनीति नहीं, मन की बात की। कहा था- इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ दिन एकांत में जाओ, अपने भीतर झांको, मन को शांत करो।

शिवराज लिखते हैं कि मोदी सिर्फ एक नेता की तरह नहीं, बल्कि बड़े भाई की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि यदि शिवराज का मनोबल टूटता है तो उसका असर लाखों कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा।

इसके बाद शिवराज उत्तराखंड गए। वहां उन्होंने गंगा किनारे आत्ममंथन किया। लौटने के बाद वे पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए। किताब के मुताबिक, उन्होंने 13-14 दिनों में 165 से ज्यादा सभाएं कीं।

मंत्री राजेश शुक्ला ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से किया संवाद

- **कार्यकर्ताओं से संवाद कर जनसमस्याओं का किया त्वरित समाधान**

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के मंत्री श्री राजेश शुक्ला ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मध्यप्रदेश शासन के मंत्री श्री राजेश शुक्ला ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी कठिनाइयों को समझा और उन्हें जल्द से जल्द समाधान दिलाने का आश्वासन दिया।

शहडोल का खूंखार हाथी ई-5 निकला दिल फेंक

नशे के इंजेक्शन पर भी बना रहा बेकाबू हथिनी के सामने आते ही हुआ शांत

शहडोल (नप्र)। मध्य प्रदेश के शहडोल-अनूपपुर वन क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आतंक मचाने वाले एक अकेले जंगली हाथी न ई-5 को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। इस हाथी पर तीन ग्रामीणों को कुचलकर मारने, मवेशियों पर हमला करने और कई घरों को तबाह करने का आरोप था।

लेकिन इस हाई-रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने वन्यजीव विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, यह हाथी स्वभाव से हिंसक नहीं था, बल्कि अपना झुंड छत्तीसगढ़ लौट जाने के कारण अकेलेपन और गहरे तनाव यानी डिप्रेशन से जूझ रहा था।

जब रामा के सामने आते ही पिघल गया

इस खतरनाक ऑपरेशन में सबसे बड़ा और जादुई मोड़ तब आया जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से रामा नाम की एक प्रशिक्षित कैंप एलीफेंट को मैदान में उतारा गया। अमूमन जंगली हाथी इंसानों या अन्य हाथियों को देखकर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन ई-5 ने जैसे ही रामा को देखा, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह दो बार खुद चलकर रामा के करीब आया और बेहद शांति से उससे बात करने की कोशिश की। वन्यजीव एक्सपर्ट्स समझ गए कि यह हाथी हमला नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव तलाश रहा था।

पहली कोशिश फेल होने के बाद रातों-रात बदली रणनीति- मुख्य वन्यजीव वार्डन डॉ. समिता राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में यह बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 22 मई को हाथी को बेहोश करने की पहली कोशिश नाकाम रही थी, क्योंकि ई-5 ने पिंजरे और जीपीएस कॉलर को तोड़ दिया था। इसके बाद वन विभाग ने रातों-रात अपनी रणनीति बदली। पालतू हाथियों और माहूतों की मदद से अगले दिन उसे सफलतापूर्वक रेडियो-कॉलर पहनाया गया और बांधवगढ़ रेंज में शिफ्ट कर दिया गया। अब उसे एक दूसरे हाथी के झुंड के करीब रखा गया है, ताकि वह दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी जी सके।

रीवा में डायल-112 गाड़ी में मंगवाई जा रही थी बीयर

- **वीडियो वायरल होते ही एडिशनल एसपी ने लिया एक्शन**

रीवा (नप्र)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से पुलिस महकमे को अचंभित करने वाला एक मामला सामने आया है। गंगेव इलाके में एक शराब दुकान के पास खड़ी डायल-112 में ऑन-ड्यूटी तैनात पुलिसकर्मियों के लिए कथित तौर पर शराब और बीयर पहुंचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद आम जनता ने पुलिस की कार्यप्रणाली और आपातकालीन सेवाओं की गंभीरता पर गंभीर सवाल उठाए। मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत प्राथमिक जांच बैठाई और दोषी पाए गए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया।

तीसरी आंख में कैद हुई करतूत- दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक शख्स शराब की दुकान से बीयर और शराब की बोतलें लेकर पास ही खड़ी डायल-112 गाड़ी की तरफ जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह शराब गाड़ी के अंदर मौजूद ऑन-ड्यूटी स्टाफ के लिए मंगवाई गई थी। शुरुआती जांच के बाद इस पूरे मामले में डायल-112 यूनिट में तैनात कांस्टेबल समर पटेल की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

सिस्टम ने ली जान!

श्योपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में बुजुर्ग ने खाया सल्फास, मौत

नहीं हो रही थी शिकायत पर सुनवाई

श्योपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश में मंगलवार के दिन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई होती है। श्योपुर में एक बुजुर्ग अपनी दुकान छुड़वाने के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहा था। उसके मामले में कही सुनवाई नहीं हो रही थी। मंगलवार को वह श्योपुर कलेक्ट्रेट में पहुंचा और सल्फास खा लिया। इसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई।

तीन बार मैं आ चुका हूं... मृतक का नाम देवेंद्र गोयल है। उन्होंने मौत से पहले कहा कि मैं तीन महीने में तीन बार आ चुका हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस घटना से श्योपुर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

दुकान पर है कब्जा- देवेंद्र गोयल के पास सब्जी मंडी के पास दुकान है। उनकी दुकान पर छोटे भाई की पत्नी और बेटे ने 28 फरवरी को कब्जा कर लिया था। इसके बाद देवेंद्र ने दो मार्च से लेकर 26 मई तक कई बार लिखित शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

कलेक्टर के अनुसार मेरे सामने केस आज ही सामने आया है। दुकान का पारिवारिक विवाद था।

तीन बार कर चुका था शिकायत

मंगलवार को भी वह अपनी पीड़ा लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। उस समय कलेक्टर शीला दाहिमा वहां मौजूद नहीं थीं। डेप्युटी कलेक्टर देवेंद्र मीणा ने उनका आवेदन लिया। इसके बाद बाहर निकलते ही देवेंद्र गोयल ने सल्फास खा लिया। इसके बाद बेहोश होकर गिर पड़े। बार-बार कहते रहे कि मैं तीन बार जनसुनवाई में आ चुका हूं। कोई सुनवाई नहीं हुई है।

सतना में बंद कमरे में मिले दंपत्ति के शव

- **पति को फंदे पर देख हार्ट अटैक आने की आशंका**
- **हत्या के बाद सुसाइड के एंगल से भी जांच**

सतना (नप्र)। सतना जिले के तिवनी गांव में बुधवार सुबह 9 बजे एक दंपति के शव उनके ही घर के कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। 45 वर्षीय रामनिवास कोरी फांसी पर लटका मिला, जबकि 43 वर्षीय पत्नी शकुंतला की लाश तख्त पर पड़ी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और मौके पर खून या शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस और एफएसएल टीम आशंका जता रही है कि पति ने पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और फिर जान दे दी, या फिर पति को फंदे पर देखकर पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हुई है।

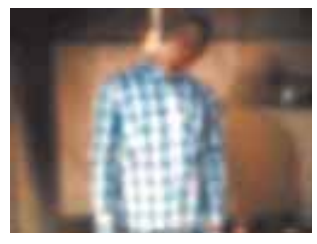

खेत से लौटे पिता ने पीछे का दरवाजा खोला- मृतक के पिता मंगल कोरी ने बताया कि वे मंगलवार रात खेत गए थे और बुधवार सुबह करीब 8 बजे घर लौटे। काफी आवाज लगाने पर जब बेटे-बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने पड़ोसी को बुलाकर किसी तरह पीछे का दरवाजा खोला। अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। शोर सुनकर घर की छत पर सो रहा 18 वर्षीय बेटा जीशू और अन्य ग्रामीण भी मौके पर जुट गए।